● वर्ष-6
● अंक-100
रायपुर, रविवार
22 नवंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-6>> बोर्ड के लिए बच्चे की...

ब्लड रिलेशन में शादी करने पर लगेगी रोक? अब देश में बनेगा नया कानून?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी से बच्चों के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान पर चिंता जाहिर की है। चीफ जस्टिस सूयकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने माना है कि रक्त संबंधों के बीच विवाह के संभावित नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है। कोट ने सीमित मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल बैंगलुरु की रहने वाली दिव्यांग लॉ स्टूडेंट ने याचिका में कहा कि उनके माता-पिता करीबी रिश्तेदार थे जिसकी वज़ह से उसे जन्मजात अनुवांशिक दिक्कत का सामना करना पड़ा। मामले को सुनते कोट ने साफ किया कि वो इस तरह की शादियों पर कोई रोक नहीं लगा सकता। इनके बारे में कानून के जरिए फैसला लेना संसद के दायरे में आता है।



सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी मोहना की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता बैंगलुरु की रहने वाली है और खुद वो लॉ की स्टूडेंट रही हैं। याचिका के द्वारा कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे रिती-रिवाज हैं और हमारे देश में ऐसी शादियां भी होती है जहां पर एक ही परिवार से जुड़े सदस्य हैं यानि जो ब्लड रिलेशन्स होता है उसी में विवाह होता है। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि बहुत सारी अनुवांशिक बीमारियां वह भी फैलती है। एक कहा जा सकता है कि इस तरह के कई मामने देखने को मिले हैं जिसका एक अच्छा खासा असर उस याचिकाकर्ता पर भी है। पीठ ने कहा हम केवल इस सीमित उद्देश्य से नोटिस जारी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाए कि क्या इस बारे में उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए या विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र सरकार को केवल इस उद्देश्य से नोटिस जारी कर सकते हैं कि वह उपयुक्त कानून बनाने की जरूरत पर विचार करे। हम उसे कोई निर्देश नहीं देंगे। हम केवल उसे इस मुद्दे के प्रति जागरूक करेंगे।'' अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि हाल के चिकित्सा अध्ययनों से पता चलता है कि रक्त-संबंधियों के बीच विवाह से उनके बच्चों में जन्मजात विकृतियों, विकासात्मक अक्षमताओं, शिशु मृत्यु और अन्य समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए लोगों को इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। वकील ने कहा कि कुछ सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि रक्त संबंधियों के बीच विवाह का चलन बढ़ रहा है। वकील ने दलील दी कि ऐसी प्रथा ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है, जहां लोग इसके नतीजों से अनजान होकर अपने चचेरे-ममेरे भाई-बहन से शादी कर लेते हैं।

एक साल पहले मैंने कहा था गोल्ड मत खरीदो, देश के पैसे बच गए, सोने की कीमतों में गिरावट को लेकर लखनऊ से मोदी का बड़ा संदेश

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारतीयों ने मई में की गई उनकी अपील पर ध्यान देते हुए सोना खरीदना कम कर दिया, जिससे सोने की कीमतों में गिरावट आई। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनकी बात मानी, उनके पैसे बचे हैं। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित पांचवें %राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह% में लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि मैंने देशवासियों से आग्रह किया था कि अगर बहुत जरूरी न हो, तो एक साल तक सोना न खरीदें। उन्होंने यह अपील लगभग छह महीने पहले, 10 मई को की थी। उन्होंने लोगों की इस प्रतिक्रिया की तुलना 1960 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री को मिली प्रतिक्रिया से की। उन्होंने कहा, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से एक समय का भोजन छोड़ने के लिए कहा था और पूरे देश ने उनकी बात मानी थी, वैसे ही मेरे देश के लोगों में आज भी वही चरित्र है। उन्होंने आगे कहा कि मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति ने लोगों से कम सोना खरीदने के लिए कहा; देशवासियों ने कम सोना खरीदा और सोने की कीमतें गिर गईं। आज लोग मुझसे कहते हैं, मोदी जी, आपने कहा, हमने आपकी सलाह मानी और हमारे पैसे बच गए।



मोदी ने सबसे पहले मई में हैदराबाद में बीजेपी की एक जनसभा में यह अपील की थी। उस समय, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थीं और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ रहा था। उन्होंने तब कहा था, सोने की खरीदारी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। देशहित में, हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम एक साल तक सोना नहीं खरीदेंगे। उस दिन उन्होंने कुल सात अपीलें की थीं, जिनमें ईंधन का कम इस्तेमाल करना और विदेश यात्राओं को टालना भी शामिल था। तीन दिन बाद, सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। 1 सितंबर को एक वीडियो संदेश में मोदी ने फिर से यही अपील दोहराई, और इस बार इसे स्वदेशी को बढ़ावा देने से जोड़ दिया। पहली अपील के अगले ही दिन ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। स्काई गोल्ड के शेयरों में 12त्न से ज्यादा, सेंको गोल्ड में लगभग 11%, कल्याण ज्वेलर्स में करीब 10% और टाइटन के शेयरों में 8% की गिरावट दर्ज की गई।

कीमती धातुओं की कीमतों में बदलाव- घरेलू कीमतें स्पष्ट रूप से कम हुई हैं। 11 मई को एमसीएक्स पर सोने की कीमत लगभग 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम थी। शुक्रवार के सत्र के अंत में यह कीमत लगभग 1.22 लाख रुपये रही, जो कि लगभग 20% की गिरावट है। अगर किसी परिवार ने मई में 10 ग्राम सोना खरीदने का फैसला टाल दिया होता, तो आज उन्हें लगभग 30,000 रुपये कम चुकाने पड़ते। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में और भी ज्यादा गिरावट आई है। 11 मई को स्पॉट गोल्ड (हाजिर सोना) लगभग 4,724 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था, जबकि शनिवार को यह 3,538 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा था - यानी इसमें लगभग 25% की गिरावट आई है। सोना अब जनवरी के अंत में बने लगभग 5,590 डॉलर के अपने रिकॉर्ड स्तर से एक-तिहाई से भी ज्यादा नीचे आ गया है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर सोने की भारी बिकवाली के पीछे अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद, 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड का 5त्न से ऊपर जाना और डॉलर का मजबूत होना मुख्य कारण हैं। उन्होंने भारतीय मांग को इसका कारण नहीं बताया है। आयात शुल्क में बढ़ोतरी और रुपये की कमजोरी के कारण भारत में सोने की कीमतें उस स्तर से ऊंची बनी हुई हैं, जितनी वे अन्यथा होतीं; यही वजह है कि वैश्विक बाजार की तुलना में घरेलू बाजार में गिरावट कम रही है।-

दो दिसंबर तक फुल हुए रामलला के ऑनलाइन वीआईपी दर्शन पास, अब 90 दिन पहले तक कर सकेंगे बुकिंग

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में कार्तिक मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच रामलला के सुगम और वीआईपी दर्शन की मांग भी बढ़ गई है। स्थिति यह है कि राम मंदिर में ऑनलाइन वीआईपी दर्शन के पास दो दिसंबर तक फुल हो चुके हैं। वहीं, आरती में शामिल होने के लिए जारी होने वाले ऑनलाइन पास भी उपलब्ध नहीं हैं। श्रद्धालुओं को अब आगे की तारीखों में पास मिलने का इंतजार करना पड़ रहा है। राम मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कार्तिक मेले के दौरान प्रतिदिन एक से सवा लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं।



7 फीसदी की रफ्तार से दौड़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, लेकिन महंगाई सिरदर्द

नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक राहत भरी और साथ ही सतर्क करने वाली खबर सामने आई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 (एफवाय27) में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च (कैपेक्स), मजबूत घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र (सर्विसेज) की तेज रफ्तार इस विकास दर को सहारा दे रही है। हालांकि, आम आदमी और उद्योग जगत के लिए महंगाई का दबाव अब भी सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, जिसके चलते आने वाले दिनों में



कर्ज और महंगे हो सकते हैं। ब्रिकवर्क रेटिंग्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत की विकास रफ्तार को घरेलू मजबूती और सेवा निर्यात का मजबूत संबल मिल रहा है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई सितंबर के 5.54 प्रतिशत से उछलकर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई, जिसने भारतीय रिजर्व बैंक के 6 प्रतिशत के सुरक्षित ऊपरी दायरे को पार कर दिया है। खाद्य महंगाई दर 8.94 प्रतिशत और सितंबर में थोक महंगाई 11.39 प्रतिशत पर दर्ज की गई। लगातार बने हुए मूल्य दबाव के कारण सख्त मौद्रिक नीति जारी रहने के आसार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई दिसंबर 2026 की समीक्षा बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) की बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे नीतिगत रेपो दर बढ़कर 5.75 प्रतिशत हो जाएगी। इसके बाद दरों में लंबे समय तक ठहराव (पॉज) आने की संभावना है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स के रिसर्च हेड राजीव शरण के अनुसार, ऊर्जा और प्रमुख कच्चे माल के आयात पर भारत की निर्भरता को देखते हुए बाहरी वैश्विक वातावरण एक अहम कारक बना हुआ है। अनिश्चितता के इस दौर में वही कंपनियां बेहतर प्रदर्शन करेंगी जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, पर्याप्त नकदी है और जो लागत के उतार-चढ़ाव को संभालने में सक्षम हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

जीएसटी की असिस्टेंट कमिश्नर डेढ़ लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

कांकेर। कांकेर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर आंचला गिरी को डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रायपुर और जगदलपुर की



संयुक्त एसीबी टीम ने 18 सदस्यीय दल के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के बाद जीएसटी विभाग में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार, कांकेर निवासी कबाड़ी व्यवसायी शोहेब रंगरेज ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि जीएसटी टैक्स के मामले में राहत देने के एवज में असिस्टेंट कमिश्नर आंचला गिरी द्वारा उनसे 1 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसीबी ने मामले की जांच की और शिकायत के आधार पर रिश्वतखोरी पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इसके बाद रायपुर एवं जगदलपुर के एसीबी अधिकारियों की संयुक्त 18 सदस्यीय टीम ने कांकेर के आदर्श नगर स्थित अधिकारी के आवास पर दबिश दी।

भगीरा एटी-1 मिसाइल का सफल परीक्षण



राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने वाहन पर तैनात एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली 'भगीरा एटी1' का सफल परीक्षण किया है। कंपनी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। 20 नवंबर को आयोजित प्रदर्शन के दौरान चार मिसाइलों का परीक्षण किया गया। इसमें भारतीय सेना, सैन्य मामलों के विभाग और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे। कंपनी के अनुसार, इस मिसाइल प्रणाली को 18 महीने के डिजाइन और विकास के बाद तैयार किया गया है। इसे भारतीय परिस्थितियों, मौसम और सैन्य जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। यह एक संपूर्ण युद्ध प्रणाली है, जिसमें मिसाइलों के साथ स्वचालित लॉन्चर, दिन और रात में लक्ष्य पहचानने वाले उपकरण तथा अदाणी डिफेंस का विकसित 4×4 बख्तरबंद वाहन शामिल है।

यूपी: गेमचेंजर प्लान से भाजपा निकालेगी जीत की राह

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने कई राज्यों में ऐन मौके पर गेमचेंजर साबित हुई नकदी योजना के जरिये राज्य की आधी आबादी को साधने की तैयारी पूरी कर ली है। पार्टी की योजना चुनावी अधिसूचना जारी होने से पूर्व बीपीएल श्रेणी के 3.64 करोड़ परिवार की एक महिला को दो किस्तों में 10-10 हजार रुपये की नकद सहायता करने की है। दिसंबर महीने में सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस श्रेणी से जुड़ी महिलाओं के जनधन बैंक अकाउंट का युद्ध स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि महिलाओं को स्वव्यवसाय शुरू करने या स्वयं सहायता समूहों से जुड़ कर भविष्य संवारने के लिए नकदी सहायता उपलब्ध कराने हेतु कई मॉडल पर बातचीत हुई। फिलहाल इस पर सहमति बनी है कि अधिसूचना जारी होने से पूर्व बीपीएल परिवार के एक महिला को दो किस्तों में 20 हजार की सहायता उपलब्ध कराई जाए। राज्य में बीपीएल श्रेणी में इस समय 3.64 करोड़ परिवार हैं। इनसे जुड़े जनधनखातों का सत्यापन का काम करीब 80त्न पूरा हो गया है। लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव में महिलाओं को नकदी वितरण संबंधी योजना शुरू करने का पार्टीशासित चार राज्यों में भाजपा का दांव सफल रहा है।

पेपर लीक मामले में मोड़: दिल्ली की विशेष अदालत ने 14 आरोपियों पर तय किए आरोप

नई दिल्ली। देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों को झकझोर देने वाले बहुचर्चित हृश्वश्वञ्ज-त्र 2026 पेपर लीक मामले में कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू स्थित एक विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने इस कथित परीक्षा घोटाले में शामिल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। हालांकि, अदालत के समक्ष सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए इन आरोपों से इनकार किया है। अब इस मामले की नियमित सुनवाई (ट्रायल) 25 नवंबर से शुरू होने जा रही है, जिसके बाद अदालत रोज़ाना आधार पर अभियोजन पक्ष के गवाहों और सबूतों को दर्ज करेगी। इस कथित परीक्षा घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो ने लगभग 20,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने 12 अगस्त को एजेंसी की शुरुआती चार्जशीट का संज्ञान लिया था। इसके बाद, 14वें आरोपी के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री (पूरक) चार्जशीट भी दाखिल की गई। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता , भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

ड्रोन से भेजे गए हथियार और हेरोइन की खेप बरामद

नई दिल्ली। पंजाब के तरनतारन जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रोन के जरिए भेजी गई हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप बरामद की है। खालड़ा सेक्टर के अंतर्गत आने वाले कलसियां गांव में बीएसएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान यह बरामदगी हुई। सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध पैकेट मिला, जिसे ड्रोन के माध्यम से गिराए जाने की आशंका है। तलाशी लेने पर उसमें से चार पिस्तौल, छह मैगजीन, 57 जिंदा कारतूस और 277 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि हथियारों और हेरोइन की यह खेप पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में भेजी गई थी। सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। ऐसे में इस बरामदगी को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए खेप किसने भेजी और इसे भारतीय सीमा में किस व्यक्ति तक पहुंचाया जाना था। बरामद हथियारों के स्रोत और तस्करी नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

भारत के उभार से डरा चीन! स रिपोर्ट में खुलासा- पाक और समंदर के रास्ते रच रहा घेराबंदी की साजिश

अभिनय आकाश

अमेरिकी कांग्रेस के एक पैनल ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन का सैन्य समर्थन, भारत के उदय को दबाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा था। पैनल ने चेतावनी दी है कि बीजिंग, नई दिल्ली के रणनीतिक प्रभाव को सीमित करने के लिए सीमा पर सैन्य दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों और समुद्री विस्तार का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग ने चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच खुफिया, समुद्री और विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्रों में गहरे सहयोग का आह्वान किया है। रिपोर्ट में एशिया में शक्ति संतुलन तय करने और बीजिंग की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को रोकने में भारत के महत्व पर भी जोर दिया गया है।

चीन का अभियान और अमेरिका के लिए भारत क्यों मायने रखता है

भारत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति का भविष्य शीर्षक वाले एक अध्याय में आयोग ने कहा कि इस्लामाबाद के साथ बीजिंग की बढ़ती सुरक्षा साझेदारी ने भारत के लिए दो मोर्चों पर युद्ध (टू-फ्रंट वॉर) की संभावना को एक गंभीर चिंता बना दिया



है। मई 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष का जिक्र करते हुए - जो जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले के बाद हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के %ऑपरेशन सिंदूर% ने दिखाया कि कैसे चीन संकट के समय सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल हुए बिना पाकिस्तान का समर्थन कर सकता है। आयोग के अनुसार, इस तरह का समर्थन पाकिस्तान के साथ भविष्य के किसी भी टकराव में भारत की सैन्य योजना को जटिल बना सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि इस्लामाबाद के साथ चीन की विकसित होती सैन्य साझेदारी ने नई दिल्ली के लिए %दो मोर्चों पर युद्ध% की स्थिति को एक अत्यंत गंभीर चिंता का विषय बना दिया है।

क्या भारत के उभार से चीन घबराया हुआ है?- आयोग ने कहा कि बीजिंग भारत के उभार को एक रणनीतिक चुनौती के रूप में देखता है और भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सैन्य, आर्थिक और समुद्री दबाव का इस्तेमाल करता है। इसमें कहा गया है कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिसके पास ऐसी जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सैन्य और भौगोलिक क्षमता है जो चीन के साथ शक्ति संतुलन को लंबे समय तक काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। रिपोर्ट में भारत की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र, परमाणु हथियारों से लैस राष्ट्र और दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक का मालिक। साथ ही, चीन के साथ भारत की 2,100 मील लंबी विवादित सीमा और हिंद महासागर के उन अहम समुद्री मार्गों पर भारत की रणनीतिक स्थिति का भी जिक्र किया गया है, जिनसे चीन की ऊर्जा और व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। हालांकि, पैनल ने यह भी चेतावनी दी है कि चीन के प्रति भारत का रुख उसके अपने रणनीतिक हितों और रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से तय होता है। इसमें कहा गया है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच करीबी रिश्ते होने का मतलब यह नहीं है कि वे अमेरिका के हर व्यापक उद्देश्य पर पूरी तरह सहमत ही होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कम सोना खरीदने की उनकी अपील मानकर लोगों ने पैसे बचाए, जिससे कीमतें घटीं।

बीजापुर नेशनल पार्क क्षेत्र में विकास की नई दस्तक



बीजापुर। कभी माओवाद के प्रभाव के चलते दुर्गम और पहुंचविहीन रहे नेशनल पार्क क्षेत्र के ग्राम पीड्डूर में नए पुलिस थाना का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर बद्रीनारायण मीणा ने जिले के 24वें थाने की शुरुआत की।

पीड्डूर में नए थाना की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्र में शासन-प्रशासन की पहुंच मजबूत करना, ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें सुगम न्याय उपलब्ध कराना है। थाना पीड्डूर के अंतर्गत कुल 15 गांवों को शामिल किया गया है। वहीं उप निरीक्षक हनीफ खान को थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। थाना खुलने से अब क्षेत्र के ग्रामीणों को अपनी शिकायत दर्ज कराने और पुलिस संबंधी कार्यों के लिए दूरस्थ थानों तक जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। स्थानीय स्तर पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ने से कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीणों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। साथ ही शासन की योजनाओं और विकास कार्यों को दुर्गम गांवों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

नेशनल पार्क क्षेत्र में नवीन थाना की शुरुआत को क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। माओवाद के प्रभाव से मुक्त होते क्षेत्र में अब प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विस्तार होने से ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने का रास्ता भी मजबूत होगा।

शुभारंभ कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य तिमेड कविता कुड़ेम, जनपद पंचायत अध्यक्ष भोपालपटनम सरिता कोरसा, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष गणपत नीलम, जनपद सदस्य दिनेश मड़े, सरपंच बड़े काकलेर सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इसके अलावा पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज बद्रीनारायण मीणा, उप महानिरीक्षक केरिपु बी.एस। नेगी, पुलिस अधीक्षक बीजापुर उमेश प्रसाद गुप्ता, कमांडेंट 214वीं वाहिनी केरिपु मनीश शर्मा, कमांडेंट 22वीं वाहिनी केरिपु रणदीप सिंह, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर सुदेश सुरवाड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविन्द्र कुमार मीणा, एसडीओपी भोपालपटनम सिद्धार्थ चौहान एवं एसडीओपी फरसेगढ़ अमन लखीसरानी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे।

शक्तिशाली आईईडी को बीडीएस टीम ने किया डिफ्यूज



कांकेर। बीडीएस (बम डिस्पोजबल स्कॉड) टीम को आज उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी, जब एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली टीम ने 3 किलो का शक्तिशाली प्रेशर आईईडी खोज निकाला। नक्सलवाद खत्म होने के ऐलान से पहले माओवादियों ने ये बम प्लांट कर रखा था।

सर्चिंग टीम में शामिल बीडीएस जवानों को जैसे ही जमीन के नीचे बम होने की खबर मिली, उन्होने इलाके की घेराबंदी कर जवानों को वहां से दूर कर दिया। इसके बाद बीडीएस टीम ने सुरक्षित तरीके से तीन किलो के प्रेशर कुकुर आईईडी को वहां से रिमूव किया। खतरे को भांपते हुए जवानों ने बम को मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया।

उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस ने बताया कि जंगल में अभी भी कई जगहों पर बम लगे हुए हैं, जिनको सुरक्षित तरीके से निकालना एक बड़ी चुनौती है। बीडीएस की टीम इस चुनौतीपूर्ण काम को बड़ी सावधान के साथ पूरा भी कर रही है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज बद्री नारायण मीणा, बीएसएफ डीआईजी दीपक तिवारी, कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा और 94वीं बटालियन बीएसएफ की टीम ने मोरखंडी हिंदूर के जंगलों में सर्चिंग अभियान चलाया था। अफसरों ने कहा कि उनका ये अभियान आगे भी तबतक जारी रहेगा जबतक पूरे खतरे को खत्म नहीं कर दिया जाता है।

धमतरी के हेड कांस्टेबल की पत्नी ने जीता मिसेज शाइन का खिताब



धमतरी। प्रतिभा और आत्मविश्वास के दम पर धमतरी की रश्मि दुबे ने प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। दिवा ऑफ छत्तीसगढ़ 2026 सीजन-7 में रश्मि ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मिसेज साइन का खिताब अपने नाम किया। साथ ही मिस टैलेंटेड का खिताब भी हासिल किया। पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर दो खिताब जीतने से परिवार में खुशी का माहौल है। अब रश्मि आगामी प्रतियोगिता के लिए गोवा जाने की तैयारी में जुटी हैं। राजधानी रायपुर के बेबीलोन इंटरनेशनल में आयोजित दिवा ऑफ छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता मिस्टर, मिसेज और टीन कैटेगरी में आयोजित की गई थी। करीब तीन महीने पहले ऑडिशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें चयनित प्रतिभागियों को दो दिवसीय आयोजन में अपनी प्रतिभा, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करने का मौका मिला।

धमतरी की रश्मि दुबे ने पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। शुरुआती ऑडिशन में चयन के बाद उन्होंने प्रदेश स्तर पर अपनी जगह बनाई और विभिन्न चरणों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए मिसेज साइन का खिताब जीत लिया। इसके साथ ही उन्हें मिस टैलेंटेड के अवार्ड से भी नवाजा गया।रश्मि दुबे ने बताया कि दिवा ऑफ छत्तीसगढ़ में उन्होंने मिसेज कैटेगरी में भाग लिया था। प्रतियोगिता में अलग-अलग प्रतिभागियों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। पहली बार ऐसे मंच पर पहुंचकर खिताब जीतना उनके लिए बेहद सकारात्मक और उत्साहजनक अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी रुचि और प्रतिभा के लिए ऐसे आयोजनों में एक बार जरूर हिस्सा लेना चाहिए, इससे खुद को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। रश्मि के पति संतोष कुमार दुबे हेड कांस्टेबल हैं।

बारिश की वजह कहीं खड़ी फसल गिरी तो कहीं कटाई कर खेत में रखा धान खराब



बलरामपुर/एमसीबी/जांजगीर-चांपा। बेमौसम बरसात ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। पहले अर्नब तूफान और अब अकवान चक्रवात से हुई बारिश ने एक बार फिर उनकी चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में भी जगह-जगह किसान परेशान हैं। जब धान बेचकर मेहनत की कमाई घर लाने का समय आया है, तब कहीं फसल जमीन पर पड़ी है तो कहीं सड़ने लगी है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पुरानडीह गांव के किसान विनोद कश्यप ने कहा कि अभी हमारी धान की फसल खेत में ही कटाई कर पड़ी है। अभी दो चक्रवाती तूफान आने की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। कुछ धान कटाई हुआ है और बाकी धान खेत में ही पड़ा हुआ है, कुछ धान तो खेत में ही झड़ गया है। पुरानडीह गांव के किसान विजय कश्यप ने भी कहा कि लगभग 2 एकड़ में धान की खेती की थी लेकिन चक्रवाती तूफान और बारिश के चलते स्थिति बहुत खराब है। मेरा करीब 80-90 हजार का नुकसान हो गया है। शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा राशि मिल जाए हम बहुत गरीब हैं और हमारा काफी नुकसान हो गया है। एमसीबी के अपर कलेक्टर लिंगराज सिदार ने बताया कि इस संबंध में जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों को सूचित कर दिया गया है। अपर कलेक्टर ने बताया कि गांवों में कोटवारों के माध्यम से सूचना प्रसारित की जा रही है। वहीं, कार्यरत पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों के माध्यम से बारिश से फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाएगा। लिंगराज सिदार ने स्पष्ट किया कि फसल नुकसान की स्थिति में शासन की ओर से निर्धारित नियमों और प्रावधानों के तहत किसानों को राहत देने की व्यवस्था है। जांजगीर चांपा जिला में भी मौसम का मिजाज बदल गया और दो दोनों तक लगातार बारिश के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त रहा। कलेक्टर ने जिले के किसानों को किसी तरह से परेशान नहीं होने की सलाह दी है। कृषि विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार जिले के किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलने का भरोसा भी दिया गया है। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर फसल नुकसान की जानकारी जुटाने और आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा के लिए प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानो को खेतों से पानी निकालने, कटे हुए फसल को सुरक्षित स्थान ले जाने और जर्मिनेश से बचाव करने की सलाह दी है।

दुर्ग में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत

- दवा कारोबारी शशांक चोपड़ा से मांगी फिरौती, पुलिस कर रही जांच



दुर्ग। छत्तीसगढ़ की उद्योग नगरी दुर्ग भिलाई से एक हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर दवा कारोबारी शशांक चोपड़ा से 15 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है। यह फिरौती व्हाट्सएप पर धमकी भरे वॉइस नोट्स के जरिए मांगी गई है। इसके अलावा कॉल भी किया गया।

धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया है। दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस केस की जांच में जुट गई है। धमकी भरा यह कॉल 19 नवंबर को आया है। पीड़ित ने बताया कि वॉइस नोट और कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया। उसके बाद उसने धमकी दी। आरोपी ने फिरौती नहीं देने के एवज में परिवार के सदस्य की हत्या करने की भी बात कही है। परिवार के सदस्य को विस्फोट से उड़ाने की भी धमकी दी है। कॉल और व्हाट्सऐप पर धमकी मिलने के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत मिलने के बाद दुर्ग पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉल करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस वॉट्सऐप पर आए वॉइस मैसेज और कॉल से जुड़े नंबरों की जांच कर रही है। इस केस में पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग की संलिप्तता से इंकार कर रही है। इस घटना के उजागर होने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। पुलिस का कहना है कि इस केस में जांच के बाद आगे कुछ कहा जा सकता है।शशांक चोपड़ा की फर्म मेडिकल उपकरण, जांच में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और स्वास्थ्य से जुड़ा सामान सप्लाई करती है। उनका नाम छत्तीसगढ़ में मेडिकल उपकरण की खरीदी से जुड़े कथित घोटाले में भी सामने आया था।

दंतेश्वरी माई के दरबार में पहुंचे 300 से ज्यादा ग्रामीण

पूजा पाठ के बाद लगाई मंदिर में अर्जी, दहशत में इस वजह से लोग

दंतेवाड़ा। कथित जादू टोने के शक में 300 से ज्यादा ग्रामीण आज मां दंतेश्वरी मंदिर के दरबार में पहुंचे और पूजा अर्चना की। पूजा के बाद ग्रामीणों ने सरपंच के साथ मंदिर में अर्जी भी लगाई। गांव वालों को कथित रुप से शक है कि जादू टोने के चलते उनपर खतरा मंडरा रहा है। इसी खतरे को दूर करने के लिए वो आज मंदिर पहुंचे। मंदिर में अर्जी लगाने वालों में भूसरास ग्राम पंचायत के सात पारा के लोग शामिल रहे। मंदिर के पुजारी विजेंद्र नाथ जिया ने सभी ग्रामीणों को सरपंच सहित क्रिया कसम खिलाया और अक्षय जल ग्रहण कराकर माता का संकल्प पूरा किया। ग्रामीणों की बीच दशकों से आस्था है कि जब भी उनपर कोई विपत्ति आती है, तब वो माता के शरण में जाते हैं। पूजा के दौरान मंदिर के पुजारी ने ग्रामीणों से कहा कि जो कोई भी गलत काम में संलग्न होगा उसके साथ माता न्याय करेंगी। भूसराम ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का कहना है, गांव की ही कोई ग्रामीण कथित रुप से जादू टोना जैसी गतिविधियों में लिप्त है। इसके जरिये वो गांव वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हम उस ग्रामीण का पता लगाने और अपने ऊपर आई विपत्ति को दूर करने के लिए यहां आए हैं। हम चाहते हैं कि माता उस आरोपी को अपने हिसाब से दंडित करें। मंदिर के पुजारी विजेंद्र नाथ जिया ने कहा, ग्रामीणों के लिए यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपनी पीड़ा और परेशानी को माता के सामने रखने का माध्यम भी है। भूसरास ग्राम पंचायत के सात पारा के ग्रामीण जादू-टोने की आशंका को लेकर 300 से अधिक की संख्या में मां दंतेश्वरी के दरबार पहुंचे हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना से मंगेश बने आत्मनिर्भर

नारायणपुर। कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देशानुसार जिले में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण हितग्राहियों तक पहुंचाने तथा उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पशुधन विकास विभाग की राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना ग्राम मातला निवासी मंगेश पोटाई के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रही है। योजना से मिली आर्थिक सहायता एवं विभागीय मार्गदर्शन के फलस्वरूप उन्होंने बकरी पालन को अपनी आजीविका का बेहतर साधन बनाया है। ग्राम पंचायत मातला, विखं नारायणपुर निवासी मंगेश पोटाई, पिता गिंजरू राम, को बकरी पालन में रुचि थी और वे इसे अपनी आय का प्रमुख साधन बनाना चाहते थे। ऐसे में राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना की जानकारी मिलने पर उन्होंने पशु चिकित्सालय बेनूर से संपर्क कर योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की। योजना के अंतर्गत उन्हें 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई।

बस्तर में वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी, रेलवे की कवायद तेज

जगदलपुर। बस्तर की रेल कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाने की दिशा में रेलवे ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। आने वाले समय में बस्तर को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल सकती है। इसके लिए जगदलपुर में ही ट्रेन के रखरखाव की सुविधा विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। जगदलपुर में कोचिंग और मेंटेनेंस डिपो बनाने के प्रस्ताव पर रेलवे काम कर रहा है। ओडिशा रेल मंडल के डीआरएम अमिताभ सिंघल ने जगदलपुर दौरे के दौरान इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। रेलवे की नई योजना के तहत जगदलपुर में कोचिंग डिपो स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। डिपो के निर्माण से भविष्य में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों के संचालन और रखरखाव की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। फिलहाल वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर अंतिम मंजूरी और आधिकारिक घोषणा होना बाकी है।

8 साल बाद फिर कैलाश गुफा में लौटी रौनक

जगदलपुर। बस्तर की तस्वीर अब धीरे-धीरे बदल रही है। कभी माओवादी हिंसा और दहशत के चलते जिन खूबसूरत पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब एक बार फिर रौनक लौटने लगी है। इसकी बड़ी मिसाल कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की कैलाश गुफा है, जो करीब 8 साल बाद फिर से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। दरअसल, बस्तर की प्राकृतिक विरासत में खास स्थान रखने वाली इस गुफा की खोज वर्ष 1993 में हुई थी। अपनी अद्भुत चूना पत्थर की संरचनाओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पहचान रखने वाली कैलाश गुफा लंबे समय तक माओवादी प्रभाव के कारण पर्यटकों की पहुंच से दूर रही। इस बदलाव की सबसे खास बात यह है कि पर्यटन की वापसी केवल सैलानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी नई संभावनाएं लेकर आई है। यहां स्थानीय युवक गाइड बनकर पर्यटकों को गुफा की विशेषताओं से रूबरू करा रहे हैं, वहीं युवतियां गार्ड के रूप में जिम्मेदारी संभाल रही हैं।

जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने डीएम ने दिए निर्देश

अम्बिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने स्कूल शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक लेकर जिले में शिक्षा व्यवस्था, विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं एवं विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, उनकी शैक्षणिक दक्षता बढ़ाने तथा बेहतर परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारी एवं शिक्षक समन्वय, प्रतिबद्धता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। बैठक में प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता एवं विकासखंडवार अपार आईडी निर्माण की स्थिति की समीक्षा की गई। आधार कार्ड निर्माण में आ रही समस्याओं वाले प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा कक्षा पहली के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र शत-प्रतिशत बनाने और विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने को कहा।

असामयिक वर्षा से फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर दें सूचना

गरियाबंद। जिले में असामयिक वर्षा एवं प्रतिकूल मौसम के कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किसानों की अधिसूचित फसलों को नुकसान होने पर किसान घटना के 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 14447 पर दर्ज करा सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि फसल क्षति होने पर निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखें, ताकि नुकसान का सर्वेक्षण और नियमानुसार बीमा दावा प्रक्रिया पूरी की जा सके। उप संचालक कृषि ने बताया कि असामयिक वर्षा, जलभराव, ओलावृष्टि एवं अन्य स्थानीय आपदाओं के कारण मक्का, उड़द, मूंग, मूंगफली, अरहर, कोदो, कुटकी एवं रागी जैसी अधिसूचित फसलों को नुकसान होने पर संबंधित बीमित किसान तत्काल सूचना दर्ज कराएं। धान की कटाई के बाद यदि फसल खेत में सुखाने के लिए रखी गई है और इस दौरान असामयिक वर्षा से नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में भी घटना के 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर पर सूचना देना आवश्यक है।

नारायणपुर मालक परिवहन संघ में कुर्सी की जंग तेज



नारायणपुर। मालक परिवहन संघ में अध्यक्ष पद की खींचतान अब सिर्फ संगठन के भीतर की उठापटक नहीं, बल्कि आरोप-प्रत्यारोप और जुबानी जंग का रूप ले चुकी है। एक तरफ संरक्षक ब्रजमोहन देवांगन और राजेश दीवान चुनाव प्रक्रिया को संगठन में स्थिरता लाने का प्रयास बताते हुए अपना पक्ष रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ वर्तमान अध्यक्ष मनीष राठौर ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही अवमानना करार देते हुए संरक्षकों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। कभी 171 सदस्यों के समर्थन से नेतृत्व परिवर्तन, कभी चुनाव की घोषणा, कभी निष्कासन के आदेश और अब वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, मालक परिवहन संघ में अध्यक्ष की कुर्सी के साथ-साथ संगठन की वैधता और हिसाब-किताब भी विवाद के केंद्र में आ गया है। दरअसल, करीब दो महीने पहले मनीष राठौर और अमित भद्र ने आपातकालीन बैठक बुलाकर 171 सदस्यों के समर्थन का दावा करते हुए पूर्व अध्यक्ष किशोर आर्य को पद से हटा दिया। इसके बाद मनीष राठौर अध्यक्ष और अमित भद्र सचिव के रूप में सामने आए। उस दौरान परिवहन कारोबार से जुड़ी समस्याओं को दो महीने में निराकरण करने का वादा किया गया, लेकिन समय बीतने के साथ संगठन के भीतर विवाद शांत होने के बजाय और गहराता चला गया। पूर्व पदाधिकारियों और वर्तमान नेतृत्व के समर्थकों के बीच तनातनी के बाद संघ के संरक्षक सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया और अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीखों की घोषणा की। इसी चुनावी प्रक्रिया को लेकर 20 नवंबर को पुराने सर्किट हाउस में संरक्षक ब्रजमोहन देवांगन और राजेश दीवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। संरक्षकों का कहना था कि संघ लगातार अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था और विवाद बढ़ने के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति निर्मित हो सकती है। उनके मुताबिक, जिला प्रशासन संघ कार्यालय को सील करने की तैयारी कर रहा था, ऐसे हालात से बचने के लिए दोनों पक्षों की सहमति से चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि संगठन को स्थायी नेतृत्व मिल सके और विवाद का पटाक्षेप हो। संरक्षकों ने मनीष राठौर की अध्यक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्हें तथाकथित अध्यक्ष तक संबोधित किया। उनका दावा है कि अध्यक्ष पद हासिल करने की प्रक्रिया में गुप्त पासवर्ड का कथित गलत इस्तेमाल किया गया और 171 सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से अध्यक्षता हासिल की गई। संरक्षकों ने संरक्षण राशि जमा नहीं होने को लेकर सफाई दी कि जब उन्हें संरक्षक बनाया गया, संरक्षकों ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव पर अब तक न्यायालय या सहायक पंजीयक से सीधे कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। यदि चुनाव को लेकर न्यायालय से स्टे मिलता है तो उसका सम्मान करते हुए चुनाव स्थगित किया जा सकता है।

जामुल नप में 1.59 करोड़ के दो टेंडर जारी



दुर्ग। दुर्ग जिले की जामुल नगर पालिका में करीब 1.59 करोड़ रुपये के दो टेंडर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर और पीआईसी सदस्यों के प्रस्ताव के बाद एसीसी अडानी सीमेंट प्लांट की टाउनशिप में रंग-रोगन, सीमेंट आर्ट, बैकलेन पेंटिंग और ड्रेन कवर के लिए 67 लाख और 92 लाख रुपये के टेंडर जारी किए गए हैं। इन टेंडरों का विरोध सत्ताधारी दल से जुड़े भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के मंडल अध्यक्ष यशवंत राजपूत ने किया है। उन्होंने नगर पालिका के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए जनता के पैसों के दुरुपयोग और कमीशनखोरी के आरोप लगाए हैं। जामुल में चुनावी गतिविधियों के बीच टेंडर जारी होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल, उपमुख्यमंत्री अरुण साव 22 नवंबर को जामुल पहुंचकर करीब 12 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करने वाले हैं। इसी बीच नगर पालिका क्षेत्र में स्थित एसीसी अडानी सीमेंट प्लांट की टाउनशिप की दीवारों के सौंदर्यीकरण के लिए जारी टेंडर विवाद का विषय बन गया है। यशवंत राजपूत ने सीएमओ रमाकांत साहू पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की दीवारों का रंग-रोगन और सौंदर्यीकरण कंपनी प्रबंधन के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से कराया जाना चाहिए। उन्होंने टेंडर जारी करने के पीछे कमीशनखोरी और आचार संहिता से पहले जल्दबाजी किए जाने के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में जामुल नगर पालिका के सीएमओ रमाकांत साहू का कहना है कि टेंडर से संबंधित सूचना नगरीय निकाय विभाग को दे दी गई है। उच्च अधिकारियों से जो निर्णय प्राप्त होगा, उसके अनुसार ही टेंडर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

सीएम हाउस में 26 को लगेगा जनदर्शन सीएम साय सुनेंगे जनता की समस्याएं

रायपुर। लंबे समय बाद फिर से छत्तीसगढ़ के



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का जनदर्शन कार्यक्रम होने जा रहा है। सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में 26 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुख्यमंत्री साय आम जनता सीधे रूबरू होंगे। इस दौरान उनकी समस्याएं, सुझाव और मांगें सुनेंगे। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री साय जनदर्शन के दौरान नागरिकों की समस्याओं को सुनने के बाद त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। जनदर्शन में आमजन अपनी समस्याओं, मांगों और सुझावों को सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकेंगे। बता दें कि लंबे वक्त के बाद 26 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन आयोजित होने वाला है। इससे प्रदेश की आम जनता को समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखने मौका मिलेगा।

भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने मुख्यमंत्री साय को लिखा पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफानों के असर से हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने प्रभावित किसानों के लिए संपूर्ण कर्जमाफी और आर्थिक सहायता की मांग उठाई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तेजराम विद्रोही ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ईमेल के जरिए पत्र भेजकर मांग की है कि फसल नुकसान झेल रहे किसानों को आरबीसी 6-4 और फसल बीमा का लाभ देने के साथ कर्जमाफी का आदेश जारी किया जाए। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष तेजराम विद्रोही ने पत्र में कहा कि पहले अर्णब तूफान, फिर मुरासु और अब अकवान चक्रवात के कारण हुई बारिश से किसानों का फसल जिसकी कटाई शुरू हो चुकी थी, जिनका करपा खेतों में पड़ा है, धान की दाने खलिहान में है और खड़ी फसल जमीन पर लोटकर सड़कर बर्बाद हो गया है। विद्रोही ने कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने अपने बयान में कहा है कि चक्रवात से प्रभावित किसानों को हरसम्भव सहायता उपलब्ध कराएगी, लेकिन पिछले दो चक्रवातों से हुई फसल नुकसान का अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है और न ही बीमा कम्पनियां किसानों के खेतों का निरीक्षण करने गया है। हम मांग करते हैं कि किसानों की सम्पूर्ण कर्जमाफ़ी की घोषणा कर आदेश जारी करें। साथ ही प्रभावित किसान परिवार की भरण पोषण के लिए आर बी सी 6-4 और बीमा का लाभ प्रदान करें।

अभनपुर जनपद अध्यक्ष की कुर्सी पर संकट! 2 दिसंबर को वोटिंग

रायपुर। रायपुर जिले की जनपद पंचायत अभनपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जनपद पंचायत अध्यक्ष चंद्रिका जितेंद्र बंजारे के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अब फैसला 2 दिसंबर को होगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए विशेष सम्मेलन बुलाने का आदेश जारी कर दिया है। इस दिन होने वाली बैठक और मतदान से तय होगा कि चंद्रिका बंजारे अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी या जनपद पंचायत में नेतृत्व परिवर्तन होगा। रायपुर कलेक्टर ने जनपद पंचायत अभनपुर के सभाकक्ष में विशेष सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर शिम्मी नाहिद को इस सम्मेलन के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रशासन की ओर से तारीख तय होने के बाद अब जनपद पंचायत की राजनीति में इस बैठक को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जनपद पंचायत अभनपुर में कुल 25 सदस्य हैं। यहां भाजपा समर्थित अध्यक्ष चंद्रिका जितेंद्र बंजारे के खिलाफ 9 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। ये सदस्य कांग्रेस समर्थित बताए जा रहे हैं। उन्होंने अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन के सामने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग रखी थी। सदस्यों की ओर से दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया था कि जनपद पंचायत में महत्वपूर्ण फैसले लेते समय निर्वाचित सदस्यों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। उनका कहना था कि निर्णय प्रक्रिया में सदस्यों की भागीदारी और सहमति को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा। इसी वजह से सदस्यों में अध्यक्ष के प्रति असंतोष बढ़ा है।

राडा का भव्य दीपावली मिलन समारोह हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ संपन्न

रायपुर। रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (राडा) द्वारा हर वर्ष की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी भव्य दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए ऑटोमोबाइल डीलर्स ने अपने परिवारजनों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह में सभी सदस्यों एवं उनके परिवारों ने एक-दूसरे को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं तथा दीप प्रज्वलित कर दीपावली की खुशियों और उल्लास को साझा किया। पूरा आयोजन दीपों की रोशनी, आपसी सौहार्द और पारिवारिक आत्मीयता से जगमगा उठा। इस अवसर पर राडा के अध्यक्ष श्री कैलाश खेमानी ने सभी सदस्यों एवं उनके परिवारजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और शिल्प परंपराओं की बिखरी अनुपम छटा

संस्कृति विभाग के संचालक डॉ. संजय कन्नौजे ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन का किया निरीक्षण

रायपुर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला, संस्कृति, परंपराओं और शिल्प कौशल की मनोहारी झलक देखने को मिल रही है। मेले में स्थापित छत्तीसगढ़ पवेलियन प्रदेश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय अस्मिता और पारंपरिक हस्तशिल्प की विशिष्ट पहचान को प्रदर्शित कर रहा है। संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के संचालक डॉ. संजय कन्नौजे ने छत्तीसगढ़ पवेलियन का निरीक्षण कर वहां प्रदर्शित विभिन्न कलाकृतियों, पारंपरिक वस्त्रों, कोसा रेशम तथा जनजातीय संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।नक्शे देखें

निरीक्षण के दौरान डॉ. कन्नौजे ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्पकला, हस्तनिर्मित उत्पादों और सांस्कृतिक विरासत के विविध स्वरूपों की जानकारी ली। उन्होंने प्रदेश के शिल्पकारों की कलात्मक प्रतिभा, परंपरागत कौशल और पीढ़ियों से संरक्षित सांस्कृतिक धरोहर के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोककला, जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक शिल्प हमारी सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण आधार हैं। इनका संरक्षण, संवर्धन और व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छत्तीसगढ़ पवेलियन में प्रदर्शित कोसा रेशम से निर्मित वस्त्र, पारंपरिक परिधान और हस्तशिल्प उत्पाद प्रदेश की विशिष्ट शिल्प परंपराओं का परिचय दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का कोसा रेशम अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता, प्राकृतिक सौंदर्य और विशिष्ट बुनाई शैली के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जनजातीय जीवनशैली से प्रेरित कलाकृतियां प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता, लोकविश्वास, परंपराओं और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव को अभिव्यक्त कर रही हैं।नक्शे देखें



डॉ. कन्नौजे ने कहा कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला जैसे प्रतिष्ठित आयोजन छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक शिल्प, हस्तनिर्मित उत्पादों और जनजातीय कलाओं को व्यापक पहचान मिलने के साथ ही स्थानीय कलाकारों एवं शिल्पकारों के लिए नए अवसरों की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत केवल हमारी ऐतिहासिक पहचान ही नहीं, बल्कि लोकजीवन, परंपराओं और सामुदायिक मूल्यों की जीवंत अभिव्यक्ति भी है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में प्रचलित लोककलाएं, पारंपरिक वस्त्र, शिल्पकला और जनजातीय परंपराएं हमारी सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाती हैं। इन परंपराओं को नई पीढ़ी से जोड़ना तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिष्ठित करना अत्यंत आवश्यक है।नक्शे देखें

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ अपनी विशिष्ट जनजातीय संस्कृति, बेलमेटल शिल्प, ढोकरा कला, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प तथा कोसा वस्त्रों के लिए विशेष पहचान रखता है। प्रदेश की पारंपरिक कलाओं में स्थानीय समुदायों की जीवनशैली, प्रकृति के प्रति आस्था और पीढ़ियों से चली आ रही कलात्मक परंपराओं की झलक दिखाई देती है। इन कलाओं का संरक्षण सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ-साथ पारंपरिक शिल्प से जुड़े समुदायों की आजीविका और आर्थिक सशक्तीकरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि, पारंपरिक शिल्प कौशल और जनजातीय अस्मिता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत को व्यापक मंच प्रदान करने के साथ ही प्रदेश की कला, संस्कृति और शिल्प परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है।

कांग्रेस की आपसी कलह पर भाजपा नेताओं का तंज

आपस में लड़कर खत्म हो जाएगी कांग्रेस पार्टी : अरुण साव

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी आपसी खींचतान को लेकर भाजपा नेताओं ने निशाना साधा है। भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के बीच विवाद पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अब कांग्रेस आपस में लड़कर खुद ही समाप्त होने वाली है। वहीं, सांसद संतोष पांडेय ने भी इस अंदरूनी खींचतान पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को मुगली घुट्टी 555 पिलाने की जरूरत बताई है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में यह सब चलता रहता है और चल ही रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल को भुगता है। अब आपस में लड़कर कांग्रेस पार्टी ही समाप्त होने वाली है।

वहीं, सांसद संतोष पांडेय ने



भी कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। दीपक बैज, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और भूपेश बघेल के बीच खींचतान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक खींचतान का दौर जारी है। कांग्रेस को फिर से मुगली घुट्टी 555 पिलाने की जरूरत है।

दरअसल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए, ढ्ढष्टष्ट सचिवों की नियुक्ति की है। फेरबदल के तहत भिलाई नगर से विधायक देवेंद्र यादव को एआईसीसी सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा विजय जांगिड समेत कुल 25 सचिवों और संयुक्त सचिवों को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटाया गया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी रहे मनीष बंछोर के सोशल मीडिया पोस्ट से बखेड़ा खड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 'बाप तो आखिर बाप होता है। जिस डाल पर बैठे हो उसी को काटोगे तो गिरना तय है। इति सिद्धम।'

मरौदा स्टेशन पर एनडीआरएफ-एसडीआरएफ ने ट्रेन हादसे से निपटने किया मॉक ड्रिल

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने मरौदा रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल की। इसमें ट्रेन हादसे के दौरान यात्रियों को बचाने और राहत पहुंचाने का अभ्यास किया गया। इसके लिए ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरने और कोच में आग लगने जैसी स्थितियां बनाई गईं। टीमों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने, घायलों को प्राथमिक इलाज देने और आग बुझाने के तरीके बताए। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ की मुंडाली (कटक, ओडिशा) बटालियन, एसडीआरएफ, रेलवे की आपदा राहत टीम, सिविल डिफेंस, स्काउट एवं गाइड और रेलवे के अलग-अलग विभागों के कर्मचारी शामिल हुए।

अभ्यास के दौरान आधुनिक उपकरणों से कोच काटकर यात्रियों



को बाहर निकालने का तरीका दिखाया गया। साथ ही आग बुझाने के अलग-अलग तरीकों का भी प्रदर्शन किया गया। रेलवे का उद्देश्य आपात स्थिति में कर्मचारियों और बचाव दल को तेजी से राहत कार्य करने के लिए तैयार रखना है। अभ्यास के दौरान प्राथमिक इलाज केंद्र, शव गृह, अधिकारी कक्ष, मीडिया केंद्र, पूछताछ केंद्र, दूरभाष केंद्र और नागरिक सुरक्षा सहायता केंद्र बनाए गए। इसके अलावा एआरटी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे सुरक्षा बल के सहायता केंद्र भी तैयार किए गए। रेलवे सुरक्षा बल के डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने बम की जांच करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ शासन और भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से अग्निशमन वाहन और एंबुलेंस भी उपलब्ध कराई गईं। स्थानीय पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की टीम भी मौजूद रही।

अपर मंडल रेल प्रबंधक बजरंग अग्रवाल ने मॉक ड्रिल में उपलब्ध बचाव उपकरणों और संसाधनों का निरीक्षण किया। उन्होंने इनकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली और वास्तविक आपदा के समय भी इसी तरह तैयार रहने की बात कही। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. सुस्कर विपुल विलासराव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि, ऐसे अभ्यास से रेलवे कर्मचारियों के साथ आम नागरिकों को भी आपदा के समय मदद करने के तरीके समझ में आते हैं।

स्व पुरुषोत्तम भाई चावड़ा की स्मृति में

छत्तीसगढ़ राज्य मास्टर्स रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता आज से

रायपुर। छत्तीसगढ़ टेबल टेनिस संघ की छत्तीसगढ़ वेटरन्स टेबल टेनिस समिति द्वारा 22 नवंबर को स्व. पुरुषोत्तम भाई चावड़ा स्मृति द्वितीय छत्तीसगढ़ राज्य मास्टर्स रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता-2026 का आयोजन सप्रे शाला टेबल टेनिस हाल, रायपुर में किया जा रहा है जिसमें पुरुष एकल (आयु वर्ग 40), पुरुष एकल (आयु वर्ग 50), पुरुष एकल (आयु वर्ग 60), पुरुष एकल (आयु वर्ग 65), पुरुष एकल (आयु वर्ग 70) एवं महिला एकल (आयु वर्ग 40), महिला एकल (आयु वर्ग 60) कुल मिलाकर 07 वर्गों में आयोजित की जा रही है जिसके लिए प्रतियोगिता स्थल एवं समस्त प्रतिभागियों हेतु सभी तैयारिया पूर्ण कर ली गई है।



उक्त प्रतियोगिता के सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ टेबल टेनिस संघ के सचिव श्री सार्थक शुक्ला ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों से कुल मिलाकर लगभग 120 खिलाड़ी एवं ऑफिसियल्स भाग ले रहे हैं एवं प्रतियोगिता लीग पद्धति में खेली जायेगी। प्रतियोगिता के उदघाटन समारोह के मुख्य अतिथि नगर पालिक निगम रायपुर के सभापति श्री सूर्यकांत राठौड़ होंगे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी अनिल चावड़ा करेंगे। प्रतियोगिता के मैच कल प्रातः 9.30 बजे से खेले जायेंगे। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक श्री प्रदीप जोशी हैं।

भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर सोशल मीडिया में सियासी जंग

ओपी ने भूपेश से कहा- 'आखिर गांधी परिवार से आगे आपको कुछ क्यों नहीं दिखता?'

■ बघेल का जवाब- 'आपकी आत्मा तो उद्योगपति के पास गिरवी है'

रायपुर। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर छत्तीसगढ़ में सियासत जोरदार गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बीच सोशल मीडिया में वार-पलटवार हो रहा है। इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जनजातीय सम्मेलन में वित्त मंत्री के दिए भाषण की कटिंग को सोशल मीडिया में पोस्ट करने के साथ हुई, जिस पर वित्त मंत्री ने पलटवार किया, जिसके जवाब में फिर से भूपेश बघेल ने हमला किया है।

दरअसल, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर धरमजयगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन जनजातीय सम्मेलन में भाषण देते वक्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी की जबान फिसल गई थी, जिसमें उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जगह भगवान बिरसा 'मुंडी' कह दिया था। भाषण के इस क्लिपिंग को भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में शेयर करते हुए लिखा कि 'भगवान बिरसा मुंडा तक का नाम तो ठीक से ले नहीं पा रहे हैं और मनाने चले हैं जनजातीय गौरव दिवस। जब मन में पाप हो तो जुबान फिसल ही जाती है।'

सोशल मीडिया पर जब बात कही



गई तो जवाब देना भी लाजिमी हो जाता है। लिहाजा ओपी चौधरी ने इस पोस्ट के जवाब में एक लंबा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, 'आपने जो सोशल मीडिया में भगवान बिरसा मुंडा जी का ,मुझे लेकर जो वीडियो पोस्ट किया है। यह आपके घटिया राजनीति के स्तर को बताता है। वैसे आप तो टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग के भी माहिर और स्तरहीन खिलाड़ी भी हैं। अपने सीबीआई केस के बारे में हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को एक बार याद दिलाइएगा तो।

वैसे आप मेरा जो वीडियो अपलोड किये हैं, उसमें मैं जो जिक्र कर रहा हूँ कि मोदी जी ने आजाद भारत में आदिवासी समाज से पहला राष्ट्रपति बनवाया। इसमें कुछ गलत है क्या? क्या आप जवाब देंगे कि आजादी के बाद कांग्रेस को 50 सालों से ज्यादा मौका मिला तो आदिवासी समाज से कोई राष्ट्रपति कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया?

उस वीडियो में मैं जिक्र कर रहा हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर को मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और आज पूरे देश में यह मनाया जाता है। क्या इसमें आपको कहीं कोई आपत्ति है? साथ में यह भी बताइयेगा कि 50 सालों से अधिक अवसर मिलने पर भी राष्ट्रनायक भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को आपके प्रधानमंत्रियों ने क्यों नहीं मनवाया? आखिर गांधी परिवार से आगे आप लोगों को क्यों नहीं दिखता?

ओपी चौधरी ने अपनी बात को कहने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखते हुए अंत में लिख डाला कि आपकी, जनता के बीच कोई एक्टिविटी न तो मुझे 15 नवंबर की दिखी और न ही उसके बाद की। भगवान बिरसा मुंडा जी को समर्पित जनता के बीच कोई कार्यक्रम किये होंगे तो मुझे जरूर भेजियेगा, मैं इंतजार करूँगा और अगर लोगों के बीच कोई कार्यक्रम नहीं किये होंगे तो आदिवासी समाज, पूरे प्रदेश और देश से जरूर माफी मांगियेगा।

अब जब बात चली है तो दूर तलक जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओपी चौधरी के पोस्ट का जवाब देते हुए अपनी भी बात विस्तार से रखी। उन्होंने जवाब में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम ग़लत लेकर अपमान आपने किया और बुरा भी आप ही मान गए। कमाल है। इसके साथ शेयर की गई फोटो कि जिक्र करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की यह जीवंत प्रतिमा बस्तर के चारामा में लगी है। विधानसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष और भानुप्रतापपुर के विधायक स्व। मनोज मंडावी जी ने यह प्रतिमा लगवाई थी। तारीख़ थी, 13-08-2022। हज़ारों लोगों की उपस्थिति में एक गरिमामय कार्यक्रम में इस मूर्ति का अनावरण हुआ था। और यह सिर्फ़ एक उदाहरण है उस समय का जब आरएसएस-भाजपा के मन में भगवान बिरसा मुंडा को लेकर प्रेम उपजना शुरु नहीं हुआ था। हमने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया इसके विवरण में कुछ नहीं धरा है। असल सवाल आदिवासियों के सम्मान का है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा कि आप लोग किस मुंह से आदिवासियों की बात करेंगे? आपकी आत्मा तो अडानी के पास गिरवी है और आप एक एक करके छत्तीसगढ़ का सारा जंगल अडानी के नाम करने पर तुले हुए हैं। कुल मिलाकर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर आयोजित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में सियासी जंग का विषय बन चुका है। वार पर पलटवार हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर नजर रखने वालों की ध्यान इस ओर है कि इस सियासी जंग में अगला तीर कौन छोड़ता है।

चक्रवाती तूफानों से किसानों का फसल बर्बाद सरकार मुआवजे का आंकलन भी नहीं करवा रही : बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुये कहा कि पिछले 24 दिनों में तीन चक्रवाती तूफानों के कारण किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। यह तीनों तूफान ऐसे समय आये है, जब किसानों की फसल तैयार हो गयी है। अभी अकवान तूफान के समय बहुत से किसानों का धान खरीदी केन्द्रो पर पहुंच चुका है। वहां पर बे-मौसम बारिश से भीग गया है। बहुत से किसानों का धान बेमौसम बारिश से गिर गया है। लाखो किसानों का धान अभी खेतो में कटकर करपा पड़ा था। बियारा तक नहीं आया है तथा भीग कर वही खराब हो गया है। बस्तर क्षेत्र में पहले ही 1083 गांवो के 74 हजार से अधिक लोग और 6154 हेक्टेयर से ज्यादा फसल प्रभावित हो चुकी है। पूरे प्रदेश में लाखों हेक्टेयर धान की फसल खराब हो चुकी है। लेकिन यह सरकार गंभीर नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले दो तूफानों अर्नव और मुरासू से हुए नुकसान के आंकलन का सर्वे सरकार की तरफ से नहीं करवाया गया है। तीसरे तूफान अकवान का अभी प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। किसानों के नुकसान के आंकलन के लिये कोई प्रयास नहीं किये जाने से सरकार की नीयत में खोट दिख रही है। अब जबकि चक्रवाती तूफान 'अकवान' आया हुआ है, बहुत से किसान धान बेचने के लिये अपना टोकन कटवा चुके थे, लेकिन तीन चार दिनों से खराब मौसम के कारण वे धान नहीं बेच पाये है, उनका टोकन लेप्स हो गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि तीनो तूफान के समय से ही पटवारी हड़ताल में है। सरकार ने इस हड़ताल को समाप्त करवाने के लिये कोई ठोस प्रयास नहीं किया। पटवारी के माध्यम से ही फसलो के नुकसान का आंकलन करवाया जाता है। पटवारियो के हड़ताल से आंकलन नहीं हो पा रहा। सरकार कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं



देख रही। मतलब फसल क्षतिपूर्ति नहीं देना चाहती है। निजी फसल बीमा कंपनिया सरकार के संरक्षण में मोटा मुनाफा कमा रही है, प्रीमियम जमा करके भी किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसान इस सरकार की बदनीयती से बर्बाद हो रहे है।

कांग्रेस पार्टी मांग करती है

● सरकार तत्काल तीनो तूफानो से हुए नुकसान का आंकलन कर के क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करें।

● बीमा कंपनियों को सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया जाये कि वे तत्काल फसलों के नुकसान का आंकलन कर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करें।

● राजस्व नियम के आपदा राहत प्रावधान के तहत राजस्व पुस्तिका 6/4 के अनुसार भी मुआवजा प्राप्त करना किसानों का अधिकार है, जिस पर ये सरकार गंभीर नहीं है।

● सभी ब्लाको में कृषि अधिकारियो को नोडल अधिकारी बना कर फसल बीमा राशि प्रदान करने बीमा कंपनियो का निगरानी कराये।

● क्षतिपूर्ति की गणना प्रति एकड़ 21 क्विंटल के उत्पादन तथा 3100 रू. प्रति क्विंटल के मूल्य से की जाये। अर्थात धान के लिये 65100 रू. प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति तत्काल घोषित करे।

● जो किसान ने तीन दिनों से टोकन कटवा कर धान नहीं बेच पाये है, उनका टोकन फिर से जारी किया जाये।

● मौसम की स्थिति को देखते हुये धान खरीदी की तिथि अभी से 15 दिन और बढ़ाने की घोषणा की जाये।

● सरकार पटवारी हड़ताल समाप्त करने के लिये तत्काल पहल करे।

पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, महामंत्री सकलेन कामदार, प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा, वंदना राजपूत, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन, ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेन्द्र पप्पू बंजारे, राजनांदगांव जिला अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, संयुक्त महामंत्री अशोक राज आहुजा, वरिष्ठ प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह उपस्थित थे।

आजम खान की रिहाई क्या गुल खिलायेगी?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

आजम खान की रिहाई का असर रामपुर तक सीमित रहने वाला नहीं है। पश्चिमी यूपी में उनका राजनीतिक प्रभाव और मुस्लिम मतदाताओं के बीच पहचान उन्हें फिर चर्चा के केंद्र में ला सकती है। उनकी वापसी सपा के पुराने मुस्लिम जनाधार को सक्रिय कर सकती है। लेकिन सवाल है कि क्या आजम खान पहले जैसा प्रभाव कायम कर पाएंगे? क्या मुस्लिम मतदाता फिर उनके नेतृत्व में एकजुट होंगे? अखिलेश यादव के लिए भी यह महत्वपूर्ण परीक्षा होगी। आजम खान को कितना राजनीतिक महत्व मिलता है, इसका असर सपा के चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है। आजम खान की वापसी के बीच असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओवैसी लंबे समय से मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल उठाते रहे हैं। उनका तर्क है कि मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन लेने वाली पार्टियां उन्हें पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी नहीं देतीं। यहीं से सपा और ओवैसी के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का सवाल उठता है। क्या आजम खान मुस्लिम मतदाताओं को सपा के साथ जोड़ने में सफल होंगे? या ओवैसी मुस्लिम नेतृत्व के लिए अलग राजनीतिक विकल्प की बहस को आगे बढ़ाएंगे? पश्चिमी यूपी में यह मुकाबला केवल दो नेताओं का नहीं, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व की दिशा का भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है। खासकर रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और सहारनपुर के कई विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या चुनावी समीकरणों को प्रभावित करती रही है। हालांकि मुस्लिम बहुल सीटों पर भी जीत का फैसला केवल धार्मिक जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार, जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दों और राजनीतिक गठबंधनों से होता रहा है। रामपुर इस राजनीति का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहां आजम खान ने लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1980 में पहली बार विधानसभा पहुंचने के बाद उन्होंने रामपुर की राजनीति में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1993 से 2022 तक अलग-अलग चुनावों में उनकी जीत और राजनीतिक सक्रियता ने रामपुर को प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में विशेष पहचान दी। आजम खान की वापसी से भाजपा की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा तेज होगी। भाजपा पहले से ही हिंदुत्व, कानून-व्यवस्था और विकास को अपने चुनावी मुद्दों में प्रमुखता दे रही है। नवंबर 2026 की रणनीतिक बैठकों के बाद पार्टी ने प्रदेशव्यापी जन आशीर्वाद यात्राओं और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की तैयारी की है।

ऐसे में सवाल है कि क्या आजम खान की सक्रियता मुस्लिम मतदाताओं की गोलबंदी के साथ हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण की राजनीति को भी हवा दे सकती है? भाजपा इस राजनीतिक घटनाक्रम को अपने पक्ष में किस तरह प्रस्तुत करती है, यह महत्वपूर्ण होगा। आजम खान की रिहाई ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वे मुस्लिम मतदाताओं को फिर सपा के साथ जोड़ पाएंगे? क्या अखिलेश यादव के साथ उनकी राजनीतिक दूरी खत्म होगी? क्या ओवैसी इस बीच मुस्लिम नेतृत्व और हिस्सेदारी की नई दावेदारी पेश करेंगे? और क्या भाजपा इस पूरे घटनाक्रम को अपने चुनावी मुद्दों में शामिल कर पाएगी? 2027 का चुनाव केवल आजम खान की राजनीतिक वापसी की परीक्षा नहीं होगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि मुस्लिम राजनीति का नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा।

शांति की आड़ में महाशक्तियों की नई बिसात

अशोक भाटिया



अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, जो केवल एक घटना को दर्ज नहीं करतीं, बल्कि आने वाले दशकों की भू-राजनीतिक दिशा तय करती हैं। चीन के शेनझेन स्थित कायलिन विला में एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान एक ही गोलमेज पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात ऐसी ही एक युगांतरकारी परिघटना है। लगभग अस्सी मिनट तक चली इस त्रिपक्षीय वार्ता के बाद जारी किए गए चार-सूत्रीय शांति घोषणापत्र को वैश्विक मीडिया के एक बड़े वर्ग द्वारा परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने और विश्व शांति की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। परंतु कूटनीति की बारीक परतों को उधेड़कर देखें, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु महाशक्तियां वास्तव में हथियारों की होड़ समाप्त करने के लिए एकजुट हुई हैं, या फिर यह 1945 के याल्टा सम्मेलन का एक नया संस्करण है, जहाँ बड़ी ताकतें बंद कमरे में बैठकर आपस में दुनिया के प्रभाव क्षेत्रों का बंटवारा करने बैठी हैं?

इस बैठक के सबसे चर्चित पहलू यानी परमाणु निरस्त्रीकरण की वास्तविकता पर गौर करना आवश्यक है। बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन और परमाणु मुक्त विश्व की वकालत की। सुनने में यह विचार अत्यंत आदर्शवादी और सुखद प्रतीत होता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक के बाद यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया कि परमाणु हथियारों को पूरी तरह छोड़ना लगभग नामुमकिन है। यही विरोधाभास इस पूरे घोषणापत्र की असलियत को उजागर करता है। यदि हम घोषणापत्र की भाषा को ध्यान से पढ़ें, तो इसमें परमाणु हथियारों की संख्या घटाने या नई हथियार संधि करने जैसा कोई ठोस और बाध्यकारी वादा नहीं है। इसमें केवल परमाणु जोखिम कम करने की बातचीत और रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने की बात कही गई है। न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति के बाद वैश्विक परमाणु नियंत्रण व्यवस्था में जो शून्य पैदा हुआ था, उसे भरने के बजाय तीनों महाशक्तियों ने केवल संवाद की औपचारिकता निभाई है। विडंबना यह है कि एक तरफ चीन परमाणु मुक्त विश्व की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ वह स्वयं अपने परमाणु शस्त्रागार का सबसे तेज गति से विस्तार कर रहा है। अमेरिका और रूस के पास पहले से ही दुनिया के नब्बे प्रतिशत से अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं। ऐसे में, बिना किसी ठोस कटौती के निरस्त्रीकरण की बातें करना वैश्विक जनमत को भ्रमित करने जैसा ही है।

शेनझेन बैठक का सबसे चौंकाने वाला और कम चर्चित पहलू वह है, जहाँ इन तीनों वैचारिक रूप से विरोधी महाशक्तियों के हित आपस में पूरी तरह मेल खाते हैं। यह पहलू है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और वैश्विक न्याय प्रणाली को कमजोर करने का साझा प्रयास। घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात तो कही गई है, लेकिन इसके साथ ही तीनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ एक अभूतपूर्व एकजुटता दिखाई है। यह किसी से छिपा नहीं है कि रूस, अमेरिका और चीन, तीनों ही अपने-अपने कारणों से अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों और संधियों की निगरानी से बाहर रहना चाहते हैं। जब विश्व की तीन सबसे ताकतवर सरकारें मिलकर किसी वैश्विक न्यायिक संस्था के अधिकारों को सीमित करने पर सहमत होती हैं, तो यह छोटे और विकासशील देशों के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि महाशक्तियां एक ऐसी व्यवस्था गढ़ना चाहती हैं, जहाँ नियम-कानून केवल कमजोर राष्ट्रों पर लागू हों, जबकि ताकतवर देश अपनी शर्तों पर दुनिया चलाएं। इसके अतिरिक्त, यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व के संकट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर इस घोषणापत्र की चुप्पी यह साबित करती है कि तीनों नेताओं ने उन विवादित विषयों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिन पर उनके बीच टकराव की संभावना थी। इसे कूटनीति की भाषा में सुविधाजनक समझौता कहा जाता है, जहाँ वास्तविक समस्याओं को हल करने के बजाय केवल अपनी छवि चमकाने वाले बिंदुओं पर सहमति बनाई जाती है।

भारत के दृष्टिकोण से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और आम नागरिकों के लिए इस त्रिपक्षीय जुगलबंदी के गहरे निहितार्थ हैं। भारत की विदेश नीति सदैव रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की पक्षधर रही है। यदि अमेरिका, रूस और चीन मिलकर किसी %बिग-थ्री% क्लब का निर्माण करते हैं, तो यह भारत के बहुध्रुवीय विश्व के सपने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। विशेष रूप से चीन की भूमिका भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। शेनझेन की मेज पर बैठकर चीन ने स्वयं को एक शांतिदूत और जिम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में पेश करने का सफल प्रयास किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उत्तरी सीमाओं पर उसकी आक्रामकता और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी विस्तारवादी नीतियां आज भी क्षेत्र की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई हैं। जब अमेरिका और रूस भी चीन को वैश्विक व्यवस्था का एक बराबर का साझेदार मानने लगते हैं, तो एशिया में शक्ति संतुलन प्रभावित होना तय है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि महाशक्तियों की इस नई दोस्ती की कीमत किसी भी रूप में एशियाई देशों की संप्रभुता या हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता को न चुकानी पड़े। इसके साथ ही, रूस के साथ भारत के पारंपरिक और भरोसेमंद संबंधों को भी इस बदलते समीकरण के बीच नए सिरे से साधने की आवश्यकता होगी।

हालांकि, इस घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा पक्ष भी है, जो भारत के हर नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी और रसोई के बजट को प्रभावित करता है। शेनझेन घोषणापत्र में तीनों महाशक्तियों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का अस्सी प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है। यदि इस सहमति के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला सुचारू बनी रहती है, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर होगी। इससे देश में महंगाई को काबू में रखने, परिवहन लागत घटाने और बुनियादी ढांचे की विकास योजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यदि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम होता है, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता आएगी, जिसका लाभ भारतीय निर्यातकों और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी मिल सकता है। साथ ही, घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का जो जिक्र किया गया है, भारत को उसका कूटनीतिक लाभ उठाते हुए अपनी स्थायी सदस्यता के दावे को और अधिक मुखरता से वैश्विक मंच पर रखना होगा।

दरअसल शेनझेन की इस ऐतिहासिक बैठक को विश्व शांति के अंतिम समाधान के रूप में देखने की भूल नहीं की जानी चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब भी महाशक्तियों ने बंद कमरों में बैठकर दुनिया की तकदीर लिखने की कोशिश की है, उसका परिणाम नए शीत युद्ध, अविश्वास या क्षेत्रीय अस्थिरता के रूप में ही सामने आया है। सच्ची और स्थायी वैश्विक शांति केवल तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के हाथ मिलाने या चार-सूत्रीय घोषणापत्र जारी करने से स्थापित नहीं हो सकती। परमाणु हथियारों का खतरा तभी समाप्त होगा, जब महाशक्तियां अपने शस्त्रागारों में वास्तविक, समयबद्ध और पारदर्शी कटौती करेंगी और इसके सत्यापन के लिए स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय निगरानी को स्वीकार करेंगी। इसके साथ ही, इक्कीसवीं सदी की किसी भी नई वैश्विक व्यवस्था में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र और ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों की आवाज को बराबर का सम्मान मिलना अनिवार्य है। शेनझेन की मेज से निकला संदेश स्पष्ट है कि दुनिया एक बड़े भू-राजनीतिक बदलाव के मुहाने पर खड़ी है, और इस बदलती बिसात पर भारत को अपनी कूटनीतिक सूझबूझ, आर्थिक मजबूती और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पहले से कहीं अधिक सतर्क और सक्रिय रहना होगा।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय



24- दिङ्नाग सम्प्रदाय का न्यायवाद

गतांक से आगे...

और यह क्षणिक स्वलक्षण ही बाह्य जगत् में अस्तित्व रखता है, और परमार्थ सत् है, क्योंकि वही अर्थक्रियात्क्षम है। अर्थात् जलाने का काम अग्नि के स्वलक्षण से हो सकता है न कि सामान्य लक्षण अर्थात् मानस अग्नि से।

दूसरा तत्त्व मानस है, अर्थात् जो केवल हमारे विचार में है, परन्तु बाह्य जगत् में नहीं है, यह सामान्य लक्षण है जिसका अर्थ है अनेक वस्तुओं को एक सामान्य या जाति के रूप में देखना।

न्याय-वैशेषिक ने कहा था सामान्य भी, अर्थात् अनेक गौओं में रहने वाला गोत्व या अनेक घटों में रहने वाला घटत्व भी एक बाह्य सत् (external reality) है।

दिङ्नाग ने इसका घोर विरोध किया, उसने कहा कि सामान्य एक मानस तत्त्व मात्र है, उसका वाह्य जगत् में कोई अस्तित्व नहीं, वह अतद्व्यावृत्ति रूप है अर्थात् गौओं में रहने वाला गोत्व कोई बाह्य सत् विधिरूप भावनदार्थ (positive entity) नहीं, प्रत्युत अनेक गौओं की-अगौ (अतद्) अर्थात् भैंस, ऊँट, हाथी आदि से भिन्न होना (व्यावृत्ति) ही उस सामान्य का स्वरूप है, और यह अतद्-व्यावृत्ति मानस धर्म है।

और क्योंकि तत्त्व दो प्रकार का है अर्थात् एक स्वलक्षण (बाह्य) और दूसरा सामान्य लक्षण मानस, इसलिये प्रमाण अर्थात् हमारा ज्ञान भी दो प्रकार का है।

एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जिससे स्वलक्षण का ग्रहण होता है, वह प्रत्यक्ष सामान्य अर्थात् आकाररहित स्वलक्षण का ग्रहण करता है इसलिये वह निर्विकल्पक होता है अर्थात् वह अतीन्द्रिय (transcendental) है। स्वलक्षण के निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को ही ग्रहण कहते हैं।

क्रमशः ...

वीर दुर्गादास राठौर



जोधपुर के निकट सालवा कलां में 13 अगस्त को आसकरण राठौड़ के घर जन्मे वीर दुर्गादास ने अजीतसिंह को राजा बनाने के बाद भी कई दिनों तक सेवा की। लेकिन 70 वर्ष से अधिक की उम्र में मारवाड़ छोड़ने का निर्णय लिया। मेवाड़ के शासक ने उन्हें एक जागीर देने को कहा, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। स्वेच्छा से मारवाड़ छोड़कर उज्जैन चले गए। शिप्रा नदी के किनारे उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम दिन गुजारे। 22 नवम्बर सन 1718 को उनका निधन हो गया।

मुगल कभी मारवाड़ पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाए थे। शाहजहां ने राजपूतों से संबंध बनाकर रखे थे। उसकी मृत्यु के बाद बादशाह बने औरंगजेब ने अपनी कुटिल नीतियों के बूते जोधपुर को हथिया लिया था। इसका नाम मोहम्मदाबाद करने की घोषणा कर दी गई। जोधपुर रियासत को खालसा घोषित कर दिया। 30 साल तक यहां कठपूतली शासक बने रहे। इस दौरान एक ही व्यक्ति था जिसने जोधपुर के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। वे थे वीर दुर्गादास राठौड़। जिसने 30 साल तक जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीतसिंह को औरंगजेब से बचाकर रखा और अंतत वापस राज गद्दी पर बैठाकर राजा जसवंतसिंह को दिया वचन निभाया था। इस दौरान दुर्गादास ने अपनी कूटनीति और शौर्य के बल पर औरंगजेब को मात दी थी।

सन 1658 में औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। उसने जोधपुर के राजा जसवंतसिंह को अपने पिता की तरह ही सेनापति बनाए रखा। उन्हें काबुल में लड़ने के लिए भेज दिया। पीछे से उनके बेटे पृथ्वीसिंह को मरवा कर जोधपुर को हथिया लिया। काबुल में यह समाचार मिलते ही गंभीर घायल जसवंतसिंह की मृत्यु हो गई। इससे पहले उन्होंने दुर्गादास राठौड़ से वचन लिया कि दूसरी रानी के गर्भ में पल रहे उनके वंश की रक्षा करेंगे और जोधपुर को मुगलों से वापस लेंगे।

दुर्गादास रानियों को लेकर जोधपुर नहीं गए। कुछ समय बाद दो कुमारों का जन्म हुआ। जिसकी जानकारी मिलते ही औरंगजेब ने यह कहकर दिल्ली बुलाया कि उनकी परवरिश खुद करेगा। दुर्गादास भांप चुके थे। दुर्भाग्य से दिल्ली जाते समय एक कुमार की मृत्यु हो गई। जबकि अजीतसिंह सकशुल थे। दिल्ली में औरंगजेब ने दुर्गादास को मनसबदारी का लालच देकर कुमार को वहीं छोड़ने का कहा। लेकिन दुर्गादास नहीं माने। बमुश्किल औरंगजेब से बचाकर अजीतसिंह को ले गए और युवावस्था तक छिपाए रखा।

औरंगजेब के मन में एक ही बात थी कि दुर्गादास कभी भी अजीतसिंह के हक के लिए हमला कर सकता है। इसलिए दुर्गादास को सूबेदार बनाकर दक्षिण में भेज दिया। लेकिन अजीतसिंह औरंगजेब को नहीं मिले। वापस आकर दुर्गादास ने मारवाड़ के राजाओं को एक करना शुरू किया। इसकी भनक लगते ही औरंगजेब ने अपने सिपाहसालार भेज दिए। जिनसे दुर्गादास का कई जगह पर युद्ध हुआ। कहा जाता है कि वो ऐसा दौर था जिसमें दुर्गादास घोड़े पर बैठ कर ही नींद लेते थे।

क्वाड और आसियान के बीच भारत की राह

आनंद कुमार



दक्षिण-पूर्व एशिया एक बार फिर भारत की विदेश नीति और सामरिक प्राथमिकताओं के केंद्र में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मनीला यात्रा और 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन तथा 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में उनकी भागीदारी संकेत है कि भारत इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस यात्रा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसके दौरान भारत, फिलीपीन और आसियान के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के साथ-साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई। मनीला में आयोजित क्वाड नेताओं की बैठक ने इस यात्रा को और अधिक सामरिक महत्व प्रदान किया।

भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के संबंधों में पिछले तीन दशकों के दौरान व्यापक परिवर्तन आया है। 1992 में आसियान के साथ क्षेत्रीय संवाद साझेदार के रूप में शुरू हुआ संबंध 1995 में पूर्ण संवाद साझेदारी, 2012 में रणनीतिक साझेदारी और 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचा। मनीला यात्रा ने स्पष्ट किया है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति अब अधिक व्यापक और रणनीतिक स्वरूप ग्रहण कर रही है। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने शांति, स्थिरता व पूर्वानुमेयता को हिंद-प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख जरूरत बताया। उन्होंने जोर दिया कि भारत और आसियान को प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग के जरिये क्षेत्र का भविष्य तय करना चाहिए। यह संदेश वर्तमान परिस्थितियों में खास महत्व रखता है, क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया के देश अमेरिका व चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण जटिल सामरिक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

सम्मेलन में भारत ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की शीघ्र समीक्षा पर भी जोर दिया, ताकि दोनों पक्षों को समान व्यापारिक लाभ मिल सके। मनीला सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत-आसियान सहयोग को नई दिशा देने के लिए कई प्रस्ताव रखे। इनमें समुद्री सहयोग, साइबर सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज, युवा आदान-प्रदान, शिक्षा, रचनात्मक उद्योग और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। स्पष्ट है कि भारत अब पारंपरिक कूटनीतिक संबंधों से आगे बढ़कर तकनीक, नवाचार व आर्थिक सुरक्षा आधारित साझेदारी विकसित करना चाहता है। भारत-आसियान साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण आयाम समुद्री सहयोग बनने जा रहा है। इस संदर्भ में फिलीपीन के साथ भारत के बढ़ते संबंध विशेष महत्व रखते हैं। दोनों देशों के सामरिक हित समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता के मुद्दे पर एक-दूसरे के करीब आए हैं। भारत के लिए फिलीपीन के साथ रक्षा और समुद्री सहयोग बढ़ाना दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी रणनीतिक उपस्थिति मजबूत करने का अवसर है।

मनीला में क्वाड नेताओं की बैठक ने इस यात्रा के सामरिक महत्व को और बढ़ा दिया। बैठक में हिंद-प्रशांत को स्वतंत्र, खुला, शांतिपूर्ण व समृद्ध बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। नेताओं ने बलपूर्वक या दबाव के जरिये क्षेत्रीय यथास्थिति बदलने के एकतरफा प्रयासों का विरोध किया। नौवहन और हवाई उड़ानों की स्वतंत्रता की रक्षा तथा सुरक्षित समुद्री व्यापार मार्गों को बनाए रखने पर भी सहमति बनी। क्वाड बिजनेस फोरम की स्थापना का प्रस्ताव इस सहयोग को सरकारी स्तर से आगे बढ़ाकर उद्योग, व्यापार और अकादमिक जगत तक विस्तारित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीक और आपूर्ति श्रृंखलाओं का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव बनाने के साधन के रूप में किया जाने लगा है। ऐसे में, भारत के लिए जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर वैकल्पिक और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। इससे बाहरी निर्भरता कम होने के साथ भारत की विनिर्माण क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा।

21वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा। क्वाड की तुलना में यह मंच अधिक समावेशी है, जहां अलग-अलग राजनीतिक और सामरिक हित रखने वाले देश संवाद कर सकते हैं। भारत की भागीदारी रेखांकित करती है कि वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में किसी एक व्यवस्था पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से सहयोग और संवाद को आगे बढ़ाना चाहता है। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में आपदा प्रबंधन पर संयुक्त वक्तव्य के तहत उपग्रह और मौसम संबंधी आंकड़ों के आदान-प्रदान, पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने, आपातकालीन मानवीय सहायता और संयुक्त अभ्यासों को तेज करने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने फिलीपीन के खालसा दीवान गुरुद्वारे का दौरा किया और उसके पुनर्विकास की आधारशिला रखी। यह गुरुद्वारा फिलीपीन में भारतीय समुदाय की ऐतिहासिक उपस्थिति और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है।

हालांकि, भारत की एक्ट ईस्ट नीति की सफलता केवल शिखर सम्मेलनों और घोषणाओं से सुनिश्चित नहीं होगी। इसके लिए व्यापार समझौतों की समीक्षा, संपर्क परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, रक्षा सहयोग और निवेश को वास्तविक परिणामों में बदलना होगा। दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन की मजबूत आर्थिक उपस्थिति को देखते हुए भारत को अपनी आर्थिक और व्यापारिक भागीदारी भी बढ़ानी होगी। 2027 भारत-आसियान संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा, जब दोनों के राजनयिक संबंधों के 35 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होंगे। आसियान की सामुदायिक दृष्टि-2045 और भारत के विकसित भारत-2047 के लक्ष्य भी दीर्घकालिक सहयोग के नए अवसर प्रदान करते हैं। चुनौती यह होगी कि महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय सहयोग को कमजोर न करे और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने के लिए विवश न होना पड़े। मनीला सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति में व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के साथ अब समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी, आर्थिक सुरक्षा और क्षेत्रीय संस्थाओं को मजबूत करने जैसे व्यापक सामरिक उद्देश्य भी शामिल हो चुके हैं। आसियान, क्वाड और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, तीनों भारत के लिए अलग-अलग, किंतु परस्पर पूरक मंच हैं। भारत को इनका उपयोग करते हुए अपने हितों और क्षेत्रीय साझेदारों की आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। मनीला की यात्रा इसी बदलती रणनीतिक सोच का संकेत है, जिसमें भारत हिंद-प्रशांत में अपनी भूमिका को अधिक प्रभावी बनाते हुए सहयोग, समावेशिता व क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देना चाहता है।

आज का इतिहास

1808 दुनिया की मशहूर ट्रैवल कंपनी थॉमस कुक एंड संस के संस्थापक थॉमस कुक का जन्म हुआ।
1830 अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग छेड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की सेना की मुख्य सदस्य झलकारी बाई का जन्म हुआ।
1920 हकीम अजमल ख़ान जामिया के पहले चांसलर बने।
1943 द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापान को हराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और चीनी शासक च्यांग काई शेक के बीच मंत्रणा हुई।
1950 अमेरिका के रिचमंड हिल्स में हुयी रेल दुर्घटना में 79 लोगों की मृत्यु हो गई।
1963 डलास (टेक्सास) में सं.रा. अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ़, केनेडी की हत्या हुई।
1967 संयुक्त राष्ट्र ने 242वां प्रस्ताव पारित करके इजरायल को जमीन वापस करने का निर्देश दिया
1968 मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को लोकसभा से स्वीकृति मिली।
1971 भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हवाई सीमाओं का उल्लंघन किया और दोनों देशों के बीच हवाई संघर्ष शुरू हुआ।
1975 जुआन कार्लोस स्पेन के राजा बने।
1986 ब्लेड रनर ऑस्कर पिस्टोरियस का जन्म हुआ।
1989 आज ही के दिन मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस, नेप्च्यून और चंद्रमा एक ही सीध में आये।
1990 ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर द्वारा त्यागपत्र की घोषणा।
1997 भारत की डायना हेडेन विश्व सुंदरी बनी।
1998 बांग्लादेश की विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ढाका की अदालत में आत्मसमर्पण किया।
2000 पाकिस्तान व ईरान पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंध।
2002 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के आयोजन के विरोध में नाइजीरिया में भड़के दंगे में सैंकड़ों लोग मारे गये।
2005 एंजेला मर्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनीं।
2006 भारत और वैश्विक कंसोर्टियन के छह अन्य देशों ने सूर्य की तरह ऊर्जा पैदा करने वाले प्राथमिक फ़्यूजन रिएक्टर की स्थापना करने के लिए पेरिस में ऐतिहासिक समझौता किया।
2007 ब्रिटेन में अवैध प्रवासी की समस्या पर काबू पाने के लिए कड़ी घोषणायें की गईं।
2008 भारती क्रिकेट टीम के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने अपना पद छोड़ने की धमकी दी। हिन्दी के प्रख्यात कवि कुंवर नारायण को वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार हेतु चुना गया।

क्या ट्रंप ने की रणनीतिक चूक और अमेरिका ने अपने लिए बढ़ा लिया संकट?

थॉमस एल फीडमैन

मैंने हाल ही में अबू धाबी में 'सर बानी यास' क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले अरब, ईरानी, इस्राइली, अमेरिकी और यूरोपीय विश्लेषकों तथा राजनयिकों के साथ कई दिन बिताए। वहां सिर्फ हैरानी या अचरज नहीं, बल्कि एक गहरे सदमे और डर का माहौल था। यह डर इस एहसास से पैदा हो रहा था कि अमेरिका और इस्राइल द्वारा शुरू किया गया युद्ध, अंततः ईरान को अपने पड़ोसियों के बीच पहले से कहीं अधिक ताकतवर न बना दे।

खाड़ी के अरब देशों ने अमेरिका से युद्ध शुरू करने को कभी नहीं कहा था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उसके पास इसे खत्म करने की स्पष्ट योजना होगी। अब उन्हें आशंका है कि अमेरिका व इस्राइल ने ऐसा संघर्ष छेड़ दिया है, जिसे या तो वे खत्म करना नहीं जानते, या फिर इसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते। और, अब इसकी सबसे बड़ी कीमत ईरान के अरब पड़ोसियों को चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में, ईरान दावा कर सकेगा कि उसने अमेरिका और इस्राइल, दोनों का डटकर मुकाबला किया और लड़ाई को बराबरी पर ला खड़ा किया। यात्रा के दौरान सबसे बड़ी बात, जो मैंने समझी, वह यह थी कि ट्रंप स्पष्ट रूप से अमेरिकी जनता को यह बताना चाहते हैं कि युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। उनका दावा है कि अमेरिका को होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल टैंकर सुरक्षित मिल रहे हैं। पर, जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है। मुझे संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के एक वरिष्ठ तेल अधिकारी ने डिजिटल मानचित्र के जरिये दिखाया कि ईरान यूएई के तेल टैंकरों पर लगातार बेहद अत्याधुनिक हमले कर रहा है। ऐसा लगभग हर दिन हो रहा है।

तेहरान ट्रंप को ऐसी स्थिति में धकेलना चाहता है, जहां उन्हें दो मुश्किल विकल्पों में से किसी एक को चुनना पड़े। पहला, ऐसा कमजोर समझौता करना, जिससे उनकी साख बच सके। इसके तहत ईरान को सुरक्षा की गारंटी और प्रतिबंधों से राहत मिल सकती है, जबकि वह होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने और परमाणु हथियार न बनाने का अस्पष्ट आश्वासन दे सकता है। दूसरा विकल्प युद्ध फिर से शुरू करना है, जो ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। पहले ही युद्ध से उनकी पार्टी को मध्यावधि चुनावों में भारी नुकसान हुआ है। युद्ध दोबारा शुरू होने पर ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सम्मेलन में एक ईरानी शिक्षाविद ने ईरान को ऐसा देश बताया, जिसके साथ लंबे समय तक संघर्ष में टिके रहना आसान नहीं होगा। विडंबना यह है कि अमेरिका आज इसी स्थिति में फंसा है। अब जबकि डेमोक्रेट्स का प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों पर नियंत्रण है, तो ईरान युद्ध को लेकर उसका रुख क्या होगा? यह सवाल बहुत-से लोगों ने पूछा। मेरा मानना है कि डेमोक्रेट्स को युद्ध का खर्च रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि, ऐसा करने पर ट्रंप हमेशा यह कह सकेंगे कि उन्होंने ईरान को घुटनों पर ला दिया था, पर डेमोक्रेट्स ने उनका साथ नहीं दिया। इसके बदले, उन्हें युद्ध की जांच करानी चाहिए,



ताकि इसकी रणनीतिक चूकों, अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को हुए नुकसान और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की भूमिका सामने आ सके। इससे लंबे समय में अमेरिका की स्थिति मजबूत होगी और ईरान पर दबाव बढ़ेगा।

एक और सवाल था कि चीन के साथ ट्रंप के असफल व्यापार युद्ध और ईरान के साथ असफल युद्ध में क्या समानता है? जवाब है-चीन के साथ व्यापार युद्ध और ईरान के साथ सैन्य संघर्ष में ट्रंप की रणनीति की एक समान कमजोरी सामने आई-बिना स्पष्ट योजना और दूरगामी आकलन के फैसले लेना। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत चीन पर टैरिफ लगाकर की। दो अप्रैल को अतिरिक्त 34 प्रतिशत शुल्क लगाने पर चीन ने भी अमेरिका पर समान टैरिफ लगा दिया और सात दुर्लभ मृदा तत्वों व उनसे बने चुंबकों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। इससे वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई और आखिरकार ट्रंप प्रशासन को समझौता करना पड़ा। बीजिंग ने स्पष्ट किया कि वह भविष्य में भी ऐसा कर सकता है। ईरान और होर्मुज के मामले में भी यही सबक सामने आया कि भू-राजनीति में विरोधी के पास भी जवाबी चाल चलने के विकल्प होते हैं।

एक सवाल यह भी था कि पहले से ही बंटा हुआ पश्चिम एशिया और टुकड़ों में टूट जाए, तो क्या होगा? मुझे याद नहीं पड़ता कि पश्चिम एशिया कभी इतना बिखरा हुआ नजर आया हो। आज यहां का लगभग हर हिस्सा छोटे-छोटे गुटों में बंटता दिख रहा है। तकनीक ने इन गुटों को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया है। नतीजतन, कोई भी देश या शक्ति इन सबको एकजुट कर युद्ध के बाद की ऐसी व्यवस्था बनाने की स्थिति में नहीं है, जिससे अमेरिका इस क्षेत्र से अपनी सैन्य मौजूदगी कम करके यहां स्थिरता कायम कर सके।

आखिरी सवाल जो पूछा गया वह यह था कि क्या आपने कुछ उम्मीद जगाने वाली बात सुनी? जवाब था 'हां'। यह बात लेबनान की 'यूनिवर्सिटी सेंट-जोसेफ' के प्रवक्ता सालेह अल-मचनौक ने कही। वह लेबनान व इस्राइल के बीच शांति के मुखर समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे पश्चिम एशिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो आपस में जुड़ा हो, समृद्ध हो, और जहां राजनीतिक व धार्मिक सहिष्णुता हो। पर, ऐसा तब तक नहीं हो सकता, जब तक हम (लेबनान) इस्राइल के खिलाफ युद्ध में उलझे रहें, क्योंकि ऐसा करना सिर्फ ईरान और लेबनान में उसके प्रॉक्सी मिलिशिया, हिज्बुल्ला के हितों को पूरा करता है। मुझे युवा फलस्तीनियों में भी कुछ ऐसा ही व्यावहारिक नजरिया देखने को मिल रहा है। वे भी चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए, यानी इस्राइल के बगल में एक फलस्तीनी राज्य बने।

अगर किसी तरह ईरान की उस पकड़ को कमजोर किया जा सके, जो 'इस्लामो-फासीवादी' की कट्टर विचारधारा के लिए आखिरी फलस्तीनी और लेबनानी को संघर्ष में झोंकने से भी पीछे नहीं हटता, और इस्राइल व हमास के चरमपंथी तत्वों के प्रभाव को भी खत्म किया जा सके, तो पूरे पश्चिम एशिया में व्यापक बदलाव और शांति की राह खुल सकती है।

ईरान के साथ यह युद्ध कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका के पास न तो कोई सहयोगी था, न कोई वैश्विक वैधता, न ही कोई 'प्लान बी', और न ही ईरान की आंतरिक स्थितियों की कोई समझ। लेकिन, यह युद्ध कैसे खत्म होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि, इसका असर पश्चिम एशिया के हर देश की राजनीति पर पड़ेगा और इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे।

बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं रोहित पवार

अमिताभ श्रीवास्तव

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा) के प्रमुख शरद पवार के पोते कर्जत-जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रोहित पवार इन दिनों कुछ अधिक सक्रिय हैं। उनकी कार्य पद्धति भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के नेताओं के लिए उस समय चिंता का कारण बन गई, जब उन्होंने पूर्व उपमुख्यमंत्री और राकांपा नेता अजित पवार की विमान दुर्घटना के मामले में सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अंदाज में एक इलेक्ट्रॉनिक परदे पर कुछ तथ्यों को प्रस्तुत किया। और मामले में ढिलाई के लिए अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया। रोहित पवार का यह आक्रामक अंदाज पहला नहीं था, इससे पहले वे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग(एमपीएससी) की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर पुणे में विद्यार्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर चुके थे। उसमें उन्हें राज्य के अनेक विपक्षी नेताओं का समर्थन मिला था। आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि एमपीएससी के चेयरमैन को छुट्टी पर भेजा गया और विस्तृत जांच के आदेश हुए। यही नहीं, दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पवार के आत्मविश्वास में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। साथ ही राकांपा में परिवार के बड़े प्रभावशाली नेताओं के अभाव के चलते राजनीति में उनकी गति कुछ इतनी तेज हुई है कि सत्ता पक्ष उसका हल नहीं ढूंढ़ पा रहा है। और वह भी परिणामों की चिंता के बिना तेज चलते जा रहे हैं। वर्ष 1985 में जन्मे रोहित पवार जन्म से बारामती से संबंध रखते हैं। उन्होंने शिक्षा-दीक्षा के बाद पहले अपने परिवार के उद्योगों में कार्य किया। उसके बाद पुणे जिला परिषद चुनाव से राजनीति में कूदे। उन्होंने बारामती तहसील की शिर्सुफल- गुणवड़ी सीट से जीत दर्ज कर अपनी सक्रियता दिखाई। उसके बाद वर्ष 2019 में दो बार से लगातार चुनाव जीत रहे तत्कालीन मंत्री भाजपा के प्रा. राम शिंदे को चुनाव में 43387 मतों से हराया। शिंदे क्षेत्र में अहिल्याबाई होल्कर के वंशज के रूप में पहचान रखते थे। इसलिए पवार की जीत महत्वपूर्ण रही। उसके बाद वर्ष 2024 में राकांपा के समीकरण बदले। रोहित पवार अपने दादा शरद पवार की अगुवाई वाली राकांपा से चुनाव में मैदान में उतरे। उनके मुकाबले फिर प्रा. शिंदे ही थे। इस बार भी उन्होंने बहुत कम अंतर 1243 मतों से, मगर जीत दर्ज की। यद्यपि राकांपा बंट चुकी थी। फिर भी चाचा अजित पवार ने उनके क्षेत्र में अपने रिश्तों के चलते भाजपा के पक्ष में प्रचार नहीं किया। चुनावी जीत के बाद स्व। पवार ने अनेक मंचों से उन्हें यह अहसास भी कराया कि यदि उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया होता तो वह जीत नहीं पाते। यहां तक कि उनकी जीत पोस्टल मतों से ही हो पाई। इन दोनों ही विचारों में एक पवार ने दूसरे की हैसियत का अहसास कराया था। परंतु यह भी तय था कि रोहित पवार भले ही अजित पवार के निशाने पर हों, लेकिन उन्हें शरद पवार का आशीर्वाद प्राप्त था। जिसकी वजह से वह एक कदम आगे चलने लगे थे। अजित पवार के निधन के बाद रोहित पवार की सक्रियता कई गुना बढ़ गई है। उन्हें पार्टी सांसद सुप्रिया सुले का समर्थन प्राप्त है। वे भले ही पार्टी के सर्वमान्य नेता न हों, लेकिन उन्हें पवार परिवार के सदस्य के रूप में महत्व मिला हुआ है। वे छात्रों के अलावा किसानों के लिए भी आंदोलन कर चुके हैं। वे अनशन पर भी बैठ चुके हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने नासिक के पालक मंत्री गिरीश महाजन को कुंभ मेले के आयोजन में हो रही गड़बड़ियों पर चुनौती दे डाली है। उन्होंने फडणवीस के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस के पहले 'मफलरमैन' का प्रचार किया, जिसकी आंच सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री छगन भुजबल तक भी पहुंची। वे फिलहाल बचे हुए हैं, लेकिन चिंतामुक्त नहीं माने जा सकते हैं। इससे साफ है कि वे राज्य सरकार के कई नेताओं से भिड़ने की इच्छा रखते हैं। सभी के लिए उनके पास 'होम वर्क' है। विपक्ष भले ही कहे कि उनकी 'पीआर टीम' उन्हें मुद्दे तैयार कर दे रही है, किंतु राज्य सरकार के लिए परेशानी तो खड़ी कर ही रही है। जिसके बचाव में अनेक नेताओं को एकसाथ उतरना पड़ता है। कुछ मामलों में कार्रवाई के लिए मजबूर भी होना पड़ता है।

बांग्लादेशी सेना ने तारिक रहमान का फैसला मानने से किया इंकार!

अभिनय आकाश

सेना का देश के प्रधानमंत्री को पौन घंटे का अल्टीमेटम सामने आता है। लाखों की भीड़ प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच कर रही है। आपके पास 45 मिनट है चाहे तो आप देश छोड़कर भाग सकती हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का इस्तीफा होता है। 5 जुलाई को भारत अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पांच साल पूरे होने के अवसर पर जम्मू कश्मीर के हालात और जश्न की खबरों में डूबा ही था कि दिन भर की गहमा गहमी के बीच एक कोड AJAX 1431 सामने आया। ये बांग्लादेश की राजधानी धाका से उड़े सी-130 हर्कुलेस एयरक्रॉफ्ट का कॉल साइन था। दरअसल, प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ती भीड़ और सेना के अल्टीमेटम के बीच ढाका से सेना का ही एक विमान उड़ता है और शेख हसीना को लेकर भारत के हिंडन एयरबेस पर लैंड होता है। तब से लेकर आज तक शेख हसीना भारत में हैं। लेकिन शेख हसीना अब अपनी सरज़मीं पर वापस जाना चाहती हैं। दिसंबर के अंत तक वे बांग्लादेश जा सकती हैं। ऐसे में भारत ने बांग्लादेश के सामने दो शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि उनके ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनमें उन्हें वकील मुहैया कराया जाए और निष्पक्षता के साथ उनके मामलों की जांच व ट्रायल हो। दूसरी शर्त यह है कि वे सेना (आर्मी) के नियंत्रण और सुरक्षा में बांग्लादेश जाएं, जिससे भारत को उनकी सुरक्षा की गारंटी मिल सके। यह तो अब तक की बात रही, लेकिन अब बांग्लादेश में अवामी लीग सड़कों पर है। वहां आज फिर वैसे ही हालात हैं जैसे 2024 में थे। बस फर्क इतना है कि तब लोग शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और आज उनके समर्थन में उतरे हैं।

तारिक रहमान की सरकार के खिलाफ



गारमेंट सेक्टर से जुड़े लगभग 40-50 लाख मज़दूर भी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। साथ ही, उस दौर में बनी नई पार्टी एनसीपी (NCP) भी फिलहाल रहमान सरकार के खिलाफ विरोध कर रही है। पिछले तीन हफ्तों से बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर में अशांति (अनरेस्ट) चल रही है और अब तक 200 से ज्यादा गारमेंट फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं। इस सेक्टर में तकरीबन 65 लाख मज़दूर काम करते हैं, जो इस महीने बेरोजगार हो जाएंगे। गारमेंट मज़दूरों ने %बीबीसी बांग्ला% को बताया है कि उनकी हालत इतनी खराब है कि वे रात को बिना खाए सो जाते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है और वेतन इतना कम है कि उन्हें खाने को भी नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही, 15 नवंबर से शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में उनके समर्थन में आंदोलन शुरू हो गया है। सरकार ने वहां पुलिस, बॉर्डर गार्ड (BGB) और %अंसार% बल को भेजा है। सरकार ने सेना को भी भेजने का अनुरोध किया था, लेकिन सेना ने जाने से साफ मना कर दिया। वहां बॉर्डर गार्ड की 41 प्लाटून तैनात की गई हैं। हमें अभी खबरें मिल रही हैं कि गोपालगंज पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी अपना सामान समेट कर वहां से जा रहे हैं। गोपालगंज में बीएनपी (BNP) के सांसद के घर में आग लगा दी गई है और देश भर में मोहम्मद यूनुस के %ग्रामीण बैंक% की अब तक 23 शाखाओं को आग के हवाले किया जा चुका है।

बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए अवामी लीग ने कल, 19 नवंबर को पूरे देश में लॉकडाउन (बंद) की घोषणा की है। कम से कम 30 जिलों में अवामी लीग का यह आंदोलन शुरू हो जाएगा। अभी यह सिर्फ गोपालगंज में है, लेकिन जल्द ही 29 अन्य जिलों में भी फैल जाएगा। पुलिस इस समय पूरी तरह से हतोत्साहित (डीमोरलाइज्ड) है, क्योंकि 2024 में कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी और उसका कोई न्याय नहीं हुआ, बल्कि हत्यारों को कानूनी छूट (इम्युनिटी) दे दी गई थी। जहां तक यूनुस की पार्टी की बात है, जिसे लोग एनसीपी कहते हैं वह सड़कों पर कहीं नजर नहीं आ रही है। जमात-ए-इस्लामी भी सड़कों पर नहीं है। जमात-ए-इस्लामी ने घोषणा की है कि यदि बीएनपी %नेशनल रिवोल्यूशनरी सरकार% की घोषणा करती है यानी सत्ता की बागडोर यूनुस के हाथों में सौंपती है। तभी जमात बीएनपी की मदद करेगी। फिलहाल न तो जमात बीएनपी के साथ है और न ही कोई अन्य दल। अवामी लीग भी सीधे तौर पर बीएनपी के खिलाफ है।

केंद्र में तो तब भी शेख हसीना ही थीं और आज भी हैं। उस वक्त भी सड़कों पर बवाल मचाया गया था और आज भी वैसा ही हो रहा है। फर्क यह है कि 2024 में लोगों को यह कहकर भड़काया गया था कि शेख हसीना की सरकार बिल्कुल बेकार है, इसे हटाओ, हम बांग्लादेश को %सोने का देश% बनाएंगे और यह करेंगे, वह करेंगे। लेकिन जब शेख हसीना चली गईं, तो पहले यूनुस के शुरुआती 18 महीनों में ही लोगों ने देख लिया कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। अभी जो फर्क ये है कि उस वक्त लोग शेख हसीना को हटाने के लिए सड़कों में आए थे और अभी लोग शेख हसीना को वापस लाने के लिए सड़कों में आए हैं क्योंकि उसको महसूस हो गया कि शेख हसीना के जमाने में बांग्लादेश की इकॉनमी प्रोस्पर कर रहा था और भारत से भी बहुत मदद मिल रही थी। भारत की 12 दिसंबर के बाद ये गंगा की जो पानी है बांग्लादेश को मिलने वाला है। यानी कि एग्रीमेंट एक्सटेंशन नहीं हुआ। तारिक रहमान के सरकार ने भारत के साथ दुश्मनी पैदा कर ली है।

हालात ऐसे बन जाएंगे कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आएंगे। और जब लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना (आर्मी) की जरूरत पड़ती है। सेना को यह महसूस हो गया है कि यह सरकार जितने भी काम कर रही है, वे सब देश के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री का आदेश मानना जरूरी तो होता है, मगर सूत्रों की मानें तो फिलहाल बांग्लादेश की सेना ऐसा नहीं कर रही है। इसकी वजह यह है कि पहले जब शेख हसीना के समय में सेना सड़कों पर उतरी थी, तो बाद में तारिक रहमान और यूनुस ने चुन-चुन कर सैन्य अधिकारियों (आर्मी ऑफिसर्स) और जनरलों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और उन्हें जेल में डलवाया। इसलिए सेना अब यह समझ रही है कि अगर वे फिर से सड़कों पर जाएंगे, तो उन्हें दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। भला कौन जेल जाना चाहता है? खबर तो ये भी है कि पुलिस भी अब आगे आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पहले उन पर भी कार्रवाई हुई और उन्हें जेल भेजा गया। यही कारण है कि सेना अभी बिल्कुल तटस्थ (न्यूट्रल) है। सेना यह समझ रही है कि जनता को भी अब यह महसूस हो गया है कि पूरे देश (कौम) के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसी वजह से सेना की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका मानना है कि यह एक नागरिक (सिविलियन) मामला है और इसे राजनेताओं को ही संभालना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि तारिक रहमान की सरकार गिरने ही वाली है।

भारत-जापान 2+2 वार्ता बेहद सफल रहा

नीरज कुमार दुबे

टोक्यो में भारत और जापान के बीच हुई 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बदलती सामरिक तस्वीर में एक नया संदेश दे दिया है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, अत्याधुनिक सैन्य तकनीक, नौसैनिक सुरक्षा और रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाई पर ले जाने का जो संकल्प दिखाया है, वह चीन की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षाओं के बीच बेहद अहम माना जा रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत और जापान अब केवल आर्थिक साझेदार नहीं, बल्कि एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाली मजबूत रणनीतिक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। इस बैठक से साफ हो गया है कि भारत अपनी कूटनीतिक सूझबूझ और सामरिक क्षमता के दम पर हिंद-प्रशांत में अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है और जापान के साथ मिलकर चीन के लिए नई रणनीतिक चुनौतियां खड़ी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

हम आपको बता दें कि टोक्यो में आयोजित इस बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को ठोस परिणामों में बदलने पर जोर दिया। खासतौर पर जापान की अत्याधुनिक तकनीक और भारत की औद्योगिक उत्पादन क्षमता को एक साथ जोड़ने की रणनीति महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने 'Design with Japan, Make in India' के तहत रक्षा विनिर्माण सहयोग को गति देने पर सहमति जताई है। इसका अर्थ है कि भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास और उत्पादन में भी बड़ी भूमिका निभाएगा।

इस वार्ता का एक बड़ा परिणाम NICORN परियोजना से जुड़े रक्षा समझौतों



को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता है। यह जहाजों पर इस्तेमाल होने वाली एकीकृत संचार एंटीना प्रणाली है। इसके अलावा दोनों देश नौसैनिक जहाजों के डिजाइन और निर्माण, समुद्र के भीतर निगरानी, मिसाइल तकनीक और पानी के नीचे इस्तेमाल होने वाली रक्षा प्रणालियों में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत और जापान ने एक-दूसरे के नौसैनिक जहाजों की मरम्मत और रखरखाव की सुविधाओं का इस्तेमाल करने की दिशा में भी तेजी लाने का फैसला किया है।

देखा जाये तो समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर यह साझेदारी चीन के लिए विशेष महत्व रखती है। हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक समुद्री व्यापारिक मार्गों पर चीन की बढ़ती सक्रियता लंबे समय से क्षेत्रीय देशों की चिंता का विषय रही है। भारत हिंद महासागर में एक प्रमुख सामरिक शक्ति है, जबकि जापान पूर्वी एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री क्षमता रखता है। दोनों देशों के बीच समुद्री सूचनाओं का आदान-प्रदान, Maritime Domain Awareness, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और माइन काउंटरमेजर्स क्षमता बढ़ाने का फैसला एक-दूसरे की सामरिक ताकत को जोड़ने जैसा है। इससे चीन के लिए समुद्री क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बिना निगरानी के आगे बढ़ाना पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

साथ ही जापानी मीडिया की रिपोर्टिंग में भी इस घटनाक्रम का चीन से जुड़ा रणनीतिक पहलू साफ दिखाई देता है। जापानी समाचार एजेंसी जिजी प्रेस की रिपोर्ट में 2+2 वार्ता के एजेंडे में चीन और उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर विचार-विमर्श को प्रमुखता दी गई है। वहीं जापान के विदेश मंत्रालय ने मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत तथा आर्थिक सुरक्षा को दोनों देशों के सहयोग के महत्वपूर्ण आधार के रूप में रेखांकित किया है। जापानी मीडिया के इस रुख से स्पष्ट है कि टोक्यो भारत को केवल एक बड़े बाजार या आर्थिक साझेदार के रूप में नहीं, बल्कि एशिया के सामरिक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के रूप में देख रहा है।

साथ ही पश्चिमी मीडिया का विश्लेषण भी इस साझेदारी की अहमियत समझने के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में जापान और चीन के बीच बढ़ते तनाव, ताइवान के मुद्दे पर टकराव और चीन द्वारा जापान के खिलाफ महत्वपूर्ण खनिजों तथा दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लेख किया है। ऐसे माहौल में भारत के साथ जापान का रक्षा और तकनीकी सहयोग उसकी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

हम आपको यह भी बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वार्ता के बाद स्पष्ट किया है कि भारत-जापान सहयोग का व्यापक उद्देश्य बहुध्रुवीय एशिया और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पुरानी रणनीतिक धारणाएं अब बदल रही हैं और देशों को अपनी सुरक्षा तथा वैश्विक हितों के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यह बयान भारत की बदलती कूटनीतिक सोच को दर्शाता है। दरअसल, भारत किसी एक शक्ति के पीछे खड़ा होने के बजाय अपने हितों के अनुरूप विभिन्न देशों के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारियां विकसित कर रहा है।

साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत-जापान रक्षा सहयोग अब केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है। जापानी लड़ाकू विमानों की पहली बार भारत में वीर गार्जियन 2026 सैन्य अभ्यास में भागीदारी, रक्षा उद्योग मंच की बैठक और तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यासों को अधिक व्यापक बनाने की पहल इस साझेदारी को वास्तविक सैन्य क्षमता में बदल रही है।

हम आपको यह भी बता दें कि भारत और जापान 2027 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक पड़ाव से पहले टोक्यो की 2+2 वार्ता ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नई सामरिक दिशा दे दी है।

बहरहाल, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हिंद-प्रशांत में अब शक्ति संतुलन केवल चीन की सैन्य क्षमता से तय नहीं होगा। भारत की भौगोलिक स्थिति, नौसैनिक ताकत, रक्षा उत्पादन क्षमता और जापान की अत्याधुनिक तकनीक मिलकर एक ऐसा रणनीतिक विकल्प तैयार कर रहे हैं, जिसकी अनदेखी बीजिंग के लिए आसान नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता यही है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए दुनिया की प्रमुख शक्तियों को भारत के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी के लिए जोड़ रहा है। टोक्यो की यह बैठक उसी दूरदर्शी कूटनीति का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है।

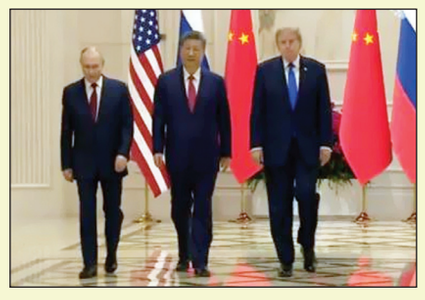
परमाणु हथियारों से लैस दुनिया की तीन महाशक्तियों का शांति घोषणापत्र

शोभना जैन

चीन के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र शेनझेन में परमाणु हथियारों से लैस दुनिया की तीन महाशक्तियों के शिखर पुरुष ट्रम्प, शी जिनपिंग और पुतिन के बीच हुई ऐतिहासिक मुलाकात और गहन मंत्रणा के बाद एक शांति घोषणापत्र जारी हुआ, जिसमें मुख्य तौर पर परमाणु हथियारों के जोखिम को कम करने की बात की गई। नेताओं ने एक मत से दोहराया कि परमाणु युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता और इसे कभी लड़ा भी नहीं जाना चाहिए।

तीनों देशों ने परमाणु जोखिमों को कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने पर आगे भी बातचीत करने का संकल्प लिया। निश्चय ही इस घोषणा पत्र से वैश्विक राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है और इस हलचल से नए समीकरण बन सकते हैं। सवाल है कि इन शिखर नेताओं के बीच गहन मंथन से वैश्विक शांति की दिशा में क्या एक नई शुरुआत हो सकती है? या फिर ये महज एक ऐसा घोषणा-पत्र बन कर रह जाएगा जो प्रतीकात्मक और डिप्लोमेटिक दिखावा ज्यादा रहा। क्योंकि इस विचार-विमर्श में कुछ ठोस नतीजे नहीं निकले,

मसलन यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संघर्ष की कोई बात ही नहीं हुई। फिर आगे भी 'बातचीत' जारी रखने के वादे और परमाणु युद्ध 'कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए' की बात करने के अलावा, बयान में बहुत कम ठोस बात सामने आई है। इस दस्तावेज में ज्यादातर 'रणनीतिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा' सुनिश्चित करने की कोशिशों का परोक्ष समर्थन किया गया है। इन तमाम बातों से हालांकि निकट भविष्य में कोई विनाशकारी संघर्ष नहीं होने की उम्मीद तो की ही



जा सकती है।

शेनझेन की यह बैठक सिर्फ तीन देशों के बीच बातचीत तक सीमित नहीं मानी जानी चाहिए। इससे ऐसी बहुध्रुवीय दुनिया की तस्वीर उभरती है, जहां बड़ी शक्तियां वैश्विक मुद्दों पर फैसले करना चाहती हैं। चीन इसे बढ़ती कूटनीतिक ताकत दिखाने के मौके के रूप में देख रहा है, जबकि रूस खोई हुई अंतरराष्ट्रीय अहमियत वापस पाना चाहता है। हालांकि इससे अमेरिका के सहयोगी देशों की चिंता बढ़ सकती है। यूक्रेन और यूरोपीय देशों को डर है कि उनकी गैरमौजूदगी में उनकी सुरक्षा से जुड़े फैसले हो सकते हैं।

भारत के लिए भी यह बैठक अहम रही, क्योंकि उसके अमेरिका और रूस- दोनों से मजबूत संबंध हैं जब कि चीन के साथ जटिल रहे हैं। नई दिल्ली अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना चाहती है। तीनों शक्तियों के बीच संपर्क भारत के लिए अवसर और चुनौतियां, दोनों ही ला सकते हैं। भारत परमाणु तनाव कम करने की कोशिशों का समर्थन करेगा, लेकिन ऐसी व्यवस्था से सतर्क रहेगा जिसमें कुछ बड़े देश मिलकर फैसले लें और दूसरे देशों के हितों को नजरअंदाज करें।

तुम्हें कितने मार्क्स मिले...?

पेपर का रिजल्ट आने पर अपने बच्चे से कभी न पूछें ये सवाल



यह बात सच्ची है कि जब आप अपने बच्चे से अक्सर 'तुम्हें कितने मार्क्स मिले?' ये सवाल पूछते हैं, तो यह कई तरह से उनकी सेल्फ-वर्थ, सिखने की प्रक्रिया और मनोदशा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आज हम आपको बताते हैं कि ये सवाल बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

क्यों यह सवाल नुकसान पहुंचाता है

जब सबसे पहला सवाल ये होता है कि 'कितने अंक आए?', तो बच्चे को यह संदेश जाता है कि अंक = मूल्य = आपकी योग्यता। पर वास्तव में 'अंक' सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम है, व्यक्ति की सम्पूर्ण क्षमता या गुण नहीं। उदाहरण के लिए, एक लेख कहता है कि यह हो सकता है कि बच्चों को यह महसूस हो जाए कि उनका पूरा मूल्य सिर्फ उनकी ग्रेड्स से तय होता है। जब यह सवाल बार-बार पूछा जाए, तो बच्चे में यह डर बन सकता है कि अगर अंक कम आए तो उन्हें मम्मा-पापा की नाराजगी या शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। यह दबाव उनकी पढ़ाई, आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

सिखने की प्रक्रिया पर ध्यान कम देना

दिए गए मार्क्स के पीछे क्या हुआ- जैसे तैयारी कैसे हुई, कौन-सी चीज मुश्किल लगी, किस तरीके से समझा जा सकता था, इन पर कम ध्यान जाता है। परिणाम पर ज्यादा फोकस होने से बच्चों में 'स्कोर करने की रणनीति' बन सकती है बजाय 'समझने की रणनीति' के। यदि संवाद का मुख्य आधार सवाल 'कितने अंक?' हो जाए, तो बच्चे हो सकता है कि उस कार्यवाही को अपेक्षा-पूर्ति के रूप में देखें- न कि खुली बातचीत के रूप में। इससे पिता-माता-बच्चा के बीच भरोसा कम हो सकता है।

बेहतर तरीका — क्या-क्या पूछा जा सकता है

- 'तुम्हारी एक्साम के दौरान सबसे कठिन क्या लगा? उस पर काम कैसे कर सकते हैं?'
- 'क्या तुमको लगता है तुमने उस विषय में सह तरीके आजमाए? अगर नहीं, तो अगली बार कैसे करोगे?'
- 'वह वो हिस्सा था जिसमें तुमने अच्छा किया? उस पर हम कैसे और सुधार कर सकते हैं?'
- 'पढ़ाई के अलावा तुम्हें क्या-क्या मजेदार लगा आज स्कूल में?'

ऐसे सवाल बच्चों की सोचना, भावनाओं को समझने और संवाद बढ़ाने में मदद करते है।

सिर्फ कुछ मिनटों में बनाएं ये पांच टेस्टी सैंडविच, बनाने का तरीका भी है बेहद आसान

शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा, जिसे सैंडविच खाना पसंद न हो। तो अगर आपको सैंडविच खाना पसंद है, तो ये खबर आपके लिए खास होने वाली है। चाहे आप ऑफिस जा रहे हों, बच्चों के टिफिन की तैयारी कर रहे हों या घर पर कुछ हल्का और टेस्टी खाना चाहते हों—सैंडविच हर मौके के लिए परफेक्ट ऑप्शन माना जाता है।

ऐसे में आज हम आपको पांच तरह के स्वादिष्ट सैंडविच की रेसिपी बताने जा रहे हैं जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में घर पर बना सकते हैं। ये न सिर्फ खाने में लाजवाब हैं बल्कि हेल्दी और एनर्जेटिक भी हैं। तो बिना जानते हैं इन्हें बनाने का आसान तरीका और खास टिप्स जिससे आपके सैंडविच बने बिल्कुल कैफे स्टाइल।

1. वेज ग्रिल सैंडविच

ये सैंडविच बनाना काफी आसान है। इसके लिए सबसे पहले तो ब्रेड पर बटर लगाएं, उसमें टमाटर, खीरा, आलू, और चटनी लगाएं। अब इसे सैंडविच मेकर में गोल्डन ब्राउन होने तक ग्रिल करें। इसे चटनी और केचअप के साथ परोसें।

2. पनीर टिक्का सैंडविच

पनीर टिक्का सैंडविच खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को मसालों और दही में मेरिनेट करें। इसके बाद इसे इसे ब्रेड के बीच में रखकर ग्रिल करें और पुदीना चटनी के साथ परोसें।

3. एग मेयो सैंडविच

अगर आपको अंडे खाना पसंद है तो आप उबले अंडे को कद्दूकस करके उसमें मेयोनेज को मिक्स करें। दोनों चीजों को मिक्स करें और फिर नमक, काली मिर्च डालें और टोस्टेड ब्रेड पर लगाएं। बस इसे फिर ग्रिल कर लें और केचअप के साथ परोसें।

4. चीज कॉर्न सैंडविच

ये सैंडविच ज्यादातर हर किसी को पसंद आता है। ये सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले स्वीट कॉर्न को उबाल लें। अब इसमें चीज और थोड़ा ऑरिगेनो मिलाएं। अब इसे इसे ब्रेड में भरकर ग्रिल करें। ये सिंपल सा सैंडविच बच्चों से लेकर बड़े भी खूब चाव से खाते है।

5. स्पाइसी चटनी सैंडविच

जो लोग तीखा खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए ये सैंडविच कमाल का है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड पर हरी चटनी फैलाएं। इसे हरी चटनी को तीखा ही रखें। अब चटनी फैलाने के बाद टमाटर और प्याज रखें। आखिर में इसे हल्का टोस्ट करें और गर्मागर्म सर्व करें।



बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चे की बेहतर तैयारी के लिए अभिभावक करें ये काम

जो बच्चे इस साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए अभिभावकों को भी कुछ तरीके अपनाने चाहिए, ताकि बच्चा बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम ला सके।



10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चे के लिए बोर्ड परीक्षा एक अहम पड़ाव होता है, जो उनके भविष्य को तय करने में मदद करता है। अच्छे अंक आने पर बेहतर कॉलेज में प्रवेश, छात्रवृत्ति और करियर के लिए क्षेत्र तय करने में मदद मिलती है। ऐसे में भारत के अधिकतर सभी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों बच्चों को बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करते है।

माता-पिता अपने बच्चे की बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे अधिक चिंतित होते हैं। ऐसे में वह बच्चे पर पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव बनाने लगते हैं। लेकिन इसका असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी होता है और अतिरिक्त दबाव उन्हें परेशान कर सकता है। बोर्ड परीक्षा बच्चों के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण होती है और इसमें अभिभावकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में जो बच्चे इस साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने के लिए अभिभावकों को भी कुछ तरीके अपनाने चाहिए, ताकि बच्चा बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम ला सके।



प्रोत्साहित करें

बच्चा दबाव में तब आता है, जब माता पिता अपनी चिंता अत्यधिक जाहिर करते हैं, वो भी नकारात्मक तरीके से। उन पर दबाव बनाने के बजाए माता पिता को बच्चे को परीक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही बच्चे के छोटे-छोटे प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करें। परीक्षा को जीवन-मरण का प्रश्न बनाने की बजाय इसे एक सीखने का अवसर मानें।

पढ़ाई की योजना बनाने में मदद करें

बच्चे के साथ मिलकर एक प्रभावी टाइम टेबल तैयार करें। टाइमटेबल ऐसा हो ताकि पढ़ाई और आराम के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके। कठिन विषयों को अधिक समय दें और पिछले साल के प्रश्न पत्र और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पहचान करें।

मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें

इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा मानसिक रूप से परेशान न हो। उसका उत्साहवर्धन करने का प्रयास करें। ऐसी बातें करें जो उसे उत्साहित करें ना कि निराश करें। जैसे 'तुम यह कर सकते हो' और 'मैं तुम्हारे साथ हूं' आदि बातें करें। बच्चे की तुलना अन्य बच्चों से न करें।

परिणाम को लेकर ज्यादा चिंता न करें

बच्चे को यह समझाएं कि मेहनत का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। परीक्षा के बाद भी उसे यह भरोसा दिलाएं कि आपका प्यार और समर्थन उसके साथ है। परिक्षा में बेहतर अंक को भविष्य के लिए एकमात्र रास्ता न बनाएं।

नियमित ब्रेक और नींद का ध्यान रखें

दिनभर पढ़ने से बच्चा होनहार नहीं हो जाएगा। जरूरी है कि हर एक दो घंटे की पढ़ाई के बाद उसे 10-15 मिनट का ब्रेक मिले। इस ब्रेक में वह दिमाग को फ्रेश करें। शारीरिक गतिविधि करें ताकि उसके दिमाग को आराम और सेहत दुरुस्त रह सके। इसके साथ ही नींद बेहतर जरूरी है। बच्चे को कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

खानपान का ध्यान रखें

बच्चे को पौष्टिक भोजन दें, जिसमें फल, सब्जियां, नट्स, और प्रोटीन शामिल हो। जंक फूड देने से बचें। ये सेहत के लिए तो नुकसानदायक होता ही है, एकाग्रता भी भंग करता है। परीक्षा से ध्यान भटकाने वाले कारकों को कम करें, जैसे बच्चे के मोबाइल और सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करें। घर का माहौल ऐसा हो जहां वह पढ़ाई के लिए ध्यान केंद्रित कर सके और शांत वातावरण में मन लगा कर पढ़ सके।

रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ध्यान दें

परीक्षा के करीब आते-आते बच्चे को पूरे सिलेबस का रिवीजन करने के लिए प्रेरित करें। समय सीमा के साथ मॉक टेस्ट दें ताकि बच्चे को परीक्षा का अनुभव हो सके।

आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करें

बच्चे को समस्याओं को खुद हल करने की आदत डालें। जब बच्चा किसी प्रश्न में अटका हो, तब उसे मार्गदर्शन दें, लेकिन उसे पूरी तरह आप पर निर्भर न बनाएं।

बच्चों में जोड़ों के दर्द के 7 संकेत, आज नजरअंदाज किया तो उम्र भर रहेंगे परेशान

बच्चों में जोड़ों से जुड़ी दिक्कतें केवल उम्रदराज लोगों में नहीं, बल्कि छोटे बच्चों में भी हो सकती हैं। कई बार माता-पिता इसे सामान्य बढ़ने का दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यदि ये दर्द बार-बार हों या रात में बढ़ जाएं, तो ये



जोड़ों की समस्या का संकेत हो सकता है। यहां बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा बताए गए 7 प्रमुख संकेत दिए गए हैं जिन्हे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

रात में बढ़ने वाला दर्द

अगर बच्चे को दिन में ठीक रहता है लेकिन रात को दर्द बढ़ जाता है, तो यह सामान्य नहीं है। ऐसा दर्द सूजन या जोड़ों में सूक्ष्म संक्रमण का संकेत हो सकता है।

चलने या दौड़ने में कठिनाई

यदि बच्चा अचानक लंगड़ाने लगे, धीरे चले या दौड़ने से बचे, तो ये संकेत है कि उसके जोड़ों में दर्द या जकड़न (ऑस्टियोआर्थराइटिस) हो सकती है।

सूजन या लालिमा

किसी एक या अधिक जोड़ों में सूजन, लालपन या गर्माहट महसूस होना सूजन (सेप्टिक आर्थ्राइटिस) का संकेत है। यह आर्थराइटिस या संक्रमण से भी हो सकता है।

सुबह उठते ही जकड़न

यदि बच्चा सुबह उठते ही अपने हाथ-पैरों को मोड़ने या सीधा करने में परेशानी बताता है, तो यह जोड़ों में सूजन या आर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है।

किसी विशेष जोड़ में बार-बार दर्द

अगर दर्द हर बार एक ही घुटने, टखने या कोहनी में हो रहा है, तो यह केवल थकान नहीं, बल्कि जोड़ों की कोई आंतरिक समस्या हो सकती है।

बुखार या थकान के साथ दर्द

अगर जोड़ों का दर्द बुखार, कमजोरी या भूख न लगने के साथ हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह संक्रमण या ऑटोइम्यून बीमारी का संकेत हो सकता है।

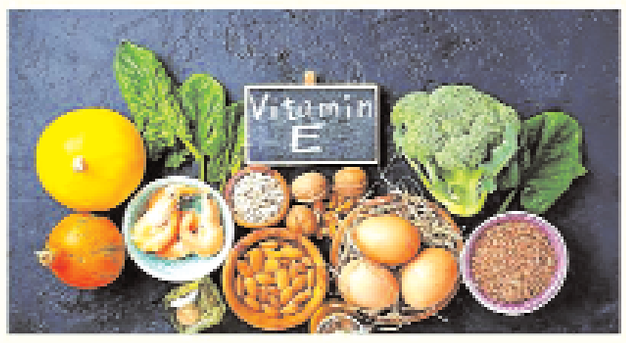
बच्चे का खेलने से बचना

यदि बच्चा पहले की तरह खेलना, कूदना या चढ़ना-उतरना छोड़ दे, तो यह दर्द से बचने की कोशिश हो सकती है।

कब डॉक्टर को दिखाएं

अगर बच्चे का दर्द 2 हफ्तों से ज्यादा बना रहे, जोड़ों में सूजन या बुखार आ जाए या फिर बच्चा लंगड़ाने लगे या चलने से बचे तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बच्चों के जोड़ों के दर्द को 'ग्रोथ पेन' मानकर टालना ठीक नहीं। जल्दी जांच कराने पर समस्या का इलाज सरल और प्रभावी हो सकता है। संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और हल्की फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के जोड़ों को मजबूत रखते है।

शुरू हो गई हैं सर्दियां, बनाकर तैयार करें ये पांच तरह के लड्डू ताकि न हो तबियत खराब



सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को अतिरिक्त पोषण और गर्माहट की जरूरत होती है। इस मौसम में हमारी इम्यूनिटी अक्सर कमजोर पड़ जाती है, जिससे सर्दी-जुकाम जल्दी हो सकती है। ऐसे में घर पर बने देसी लड्डू न केवल स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं। पारंपरिक तरीके से बनाए गए लड्डू शरीर को एनर्जी, गर्मी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं।

सर्दी के मौसम में कुछ खास तरह के लड्डू पाचन को बेहतर बनाते हैं, जोड़ों के दर्द से राहत देते हैं और शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। अगर आप ठंड में स्वस्थ और एक्टिव रहना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में इन देसी लड्डुओं को जरूर शामिल करें। आइए जानते हैं ऐसे पांच तरह के लड्डू जो सर्दियों में आपकी तबीयत खराब होने से बचा सकते हैं।

तिल-गुड़ के लड्डू

तिल और गुड़ का मेल सर्दियों में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये शरीर को गर्म रखता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाता है। इसमें कैल्शियम और आयरन भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है।

गोंद के लड्डू

गोंद से बने लड्डू जोड़ों के दर्द और ठंड से होने वाली कमजोरी में फायदेमंद होते हैं। इसमें घी, मेवा और गेहूं का आटा मिलाकर बनाया जाता है जो एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है।

मेथी के लड्डू

मेथी के लड्डू सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। महिलाओं के लिए ये खासतौर पर फायदेमंद माने जाते हैं क्योंकि ये हॉर्मोनल बैलेंस को भी सपोर्ट करते हैं।

मूंगफली के लड्डू

मूंगफली प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसके लड्डू ठंड के मौसम में ऊर्जा प्रदान करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। गुड़ के साथ मिलाकर खाने से ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों बन जाते हैं।

सूखे मेवे के लड्डू

बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश और खजूर से बने लड्डू विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। ये शरीर को ताकत देते हैं और स्किन ग्लोइंग बनाए रखते हैं। तो आप चाहें तो इसे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं।



राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

अनुच्छेद 370 हटने से घाटी में खत्म हुआ अलगाववाद : शाह

ईटानगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद, कश्मीर घाटी में अब कोई भी स्थानीय आतंकी सक्रिय नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में जो भी आतंकी अभी सक्रिय हैं, वे सभी विदेशी हैं। अरुणाचल प्रदेश के बांदरदेवा में प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर्स पुरस्कार समारोह में बोलते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आखिरी सक्रिय आतंकी को मार गिराया है। उन्होंने कहा कश्मीर के पुलवामा में, कश्मीर पुलिस ने एक एनकाउंटर में लश्कर से जुड़े आखिरी सक्रिय कश्मीरी आतंकी को ढेर कर दिया। कश्मीर घाटी की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की तुलना 1990 के दशक की उथल-पुथल से करते हुए, शाह ने आगे कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से कश्मीरी युवाओं के बीच अलगाववादी भावनाएं खत्म हो गई हैं।



संसद के मानसून सत्र का 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं

नईदिल्ली। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं किया है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। वहीं, महिला आरक्षण कानून को लागू करने और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर असमंजस बरकरार है। संसद के दोनों सदनों की बैठक 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन शनिवार सुबह तक न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का सत्रावसान किया गया है। इससे पहले वर्ष 2008 में संसद सत्र का 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था। सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के मकसद से संसद का विशेष या विस्तारित सत्र बुलाने की संभावना पर विचार कर रही है। सूत्रों ने पिछले दिनों उम्मीद जताई थी कि विधेयक लोकसभा में 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो जाएगा।



प्रधानमंत्री पर टिप्पणी: रिजिजू का राहुल को तीखा जवाब!

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी की समझौता करने वाले प्रधानमंत्री वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए रिजिजू ने विपक्षी पार्टी के सामने चार कड़े सवाल रखे। इन सवालों में 1962 के भारत-चीन युद्ध में हुए नुकसान के लिए माफी मांगने से लेकर दशकों तक देश को गरीबी और धीमी आर्थिक विकास दर में रखने के मुद्दे शामिल हैं। एक्स पर एक पोस्ट में रिजिजू ने कहा, कांग्रेस को 4 सवालों के जवाब देने चाहिए: 1. 1962 में मेरे गांव पर चीन ने कब्जा कर लिया था। क्या कांग्रेस 1962 के अपमान के लिए माफी मांगेगी? 2. कांग्रेस ने भारत को एक गरीब देश बनाए रखा। क्यों? 3. भारत को सपेरों का देश क्यों कहा जाता था? 4. भारत की अर्थव्यवस्था को हिंदू विकास दर कहकर अपमानित क्यों किया गया?



मायावती के पुराने गढ़ में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी

लखनऊ। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी-कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के बीच राजनीतिक साझेदारी अब और अधिक स्पष्ट चुनावी रूप लेती जा रही है। शनिवार को ओवैसी का सहारनपुर दौरा, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले ज़मीनी स्तर पर अपनी पैठ बनाने के इस गठबंधन के प्रयासों में एक अहम कदम है। ओवैसी, छुटमलपुर में आज़ाद के आवास पर उनसे मुलाक़ात करेंगे, जहाँ दोनों नेताओं के बीच लंच के दौरान राजनीतिक चर्चा होने की उम्मीद है। इस दौरे में एक मस्जिद से जुड़े मुद्दे पर ज़िला प्रशासन के साथ बातचीत और एक मदरसे का दौरा भी शामिल है। सहारनपुर का यह कार्यक्रम 14 नवंबर को मेरठ में हुए गठबंधन के पहले बड़े सार्वजनिक प्रदर्शन के बाद हुआ है। वहां ओवैसी ने एक आक्रामक राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि मोर्चा का तत्काल लक्ष्य 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में वापस आने से रोकना है।



आजम खां के तेवरों से उत्तरप्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राजनीतिक बिसात पर आजम खां की तंजभरी बयानबाजी में नए समीकरणों की आहट सुनाई देने लगी है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता के बीच सपा नेता आजम खां के जेल से बाहर आने के बाद इस बात की बहस हो रही है कि यह सपा के लिए कितना फायदेमंद होगा। अभी आजम खां ने उस तरह की शोलाबयानी नहीं की है जिसके लिए वह मशहूर रहें हैं, अभी तो उन्होंने हैदराबादी बिरयानी का जिक्र कर ओवैसी पर हल्का सा निशाना साधा है। अब इसे हैदराबादी रयानी बनाम आजम के पुलाव की सियासी लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। आजम खां ने ओवैसी को लेकर जिस अंदाज में टिप्पणी की, उससे साफ है कि दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक और व्यक्तिगत दूरी का मुद्दा जाहिर हो गया है। एक ओर आजम ने ओवैसी के लिए मौलाना शब्द के इस्तेमाल पर यहां तक कह दिया कि वो बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं हैं। आजम की सक्रियता और ओवैसी पर उनकी टिप्पणी मुस्लिम राजनीति गर्माने लगे हैं, साथ इसमें दावेदारी को लेकर भी नए समीकरण बन सकते हैं।



आईआईटी खड़गपुर में बोले प्रधानमंत्री

मैं चुनौतियों को चुनौती दिए बिना रह नहीं सकता

खड़गपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीयों से आग्रह किया कि वे सीमित करने वाली धारणाओं को त्यागें और खुद लगाई गई सीमाओं से आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर निर्माण, गरीबी कम करने और वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्रों में भारत की प्रगति यह साबित करती है कि देश में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों से पार पाने की क्षमता है। 21 नवंबर, 2026 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश अब उस मानसिकता से बाहर निकल चुका है जो सीमाओं को स्वीकार कर लेती थी। बाधाओं के प्रति अपने निजी दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मेरे स्वभाव में ही है कि मैं किसी चुनौती को चुनौती दिए बिना नहीं रह सकता। सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत के समय उठे उन सवालों को याद करते हुए कि क्या भारत ने इस क्षेत्र में बहुत देर से कदम रखा है- जहां दशकों से वैश्विक कंपनियों का दबदबा रहा है- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने पुरानी देरी को देश की प्रगति में बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने बताया कि चार वर्षों के भीतर देश भर में कई सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित की गई हैं, भारत ने चिप्स का निर्यात शुरू कर दिया है, और आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र इन परियोजनाओं का नेतृत्व करने और उन्हें पूरा करने में मदद कर रहे हैं।

जब मैंने सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया, तो कई सवाल उठाए गए। लोगों ने पूछा, अभी इस मिशन की क्या ज़रूरत है? दूसरे देश तो पहले से ही इनका निर्माण कर रहे हैं, और



सेमीकंडक्टर तो पिछले 50 सालों से बन रहे हैं। अब इनका निर्माण करके हमें क्या हासिल होगा? इस तरह की बातें कही जा रही थीं जो एक सीमित सोच को दर्शाती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं दृढ़ था। मैंने पूछा, अगर पहले इसमें देरी हुई, तो क्या हुआ? क्या भारत को हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? हमने पहल की। मैंने खुद अधिकारियों के साथ मिलकर एक योजना तैयार की और आज नतीजा देखिए: महज़ चार सालों के भीतर, पूरे देश में कई सेमीकंडक्टर इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत ने अब चिप्स का निर्यात भी शुरू कर दिया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था, जो नवंबर 2026 से लगभग पाँच साल पहले का समय है, न कि महज़ चार साल (और 2021 के चार साल बाद 2025 आता है)। इसके अलावा, हालाँकि भारत ने कई सेमीकंडक्टर निर्माण, पैकेजिंग/ओएसएटी और फैब्रिकेशन इकाइयों को मंज़ूरी दी है और यहाँ लंबे समय से डिज़ाइन/निर्यात गतिविधियाँ चल रही हैं, लेकिन हाल ही में मंज़ूर किए गए घरेलू फैब्रिकेशन/पैकेजिंग संयंत्रों से व्यावसायिक उत्पादन और निर्यात, उनके निर्माण और उत्पादन की चरणबद्ध समय-सीमा पर निर्भर करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीकी महत्वाकांक्षा को सोच में बदलाव से जोड़ते हुए, व्यक्तिगत प्रतिभा, सपनों या राष्ट्रीय क्षमता पर सीमाएं न लगाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक रुकी हुई सोच सच्ची प्रगति में बाधा डालती है, जबकि देश अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़कर ही अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अक्सर लोग अपनी सोच पर खुद ही सीमाएं लगा लेते हैं—वे अपने लिए दायरे तय कर लेते हैं—और इन्हें ही हम सीमित करने वाली धारणाएं (limiting beliefs) कहते हैं। इन धारणाओं का क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने सपनों, अपनी प्रतिभा और यहां तक कि अपने देश की क्षमता पर भी सीमाएं लगा देना। उन्होंने आगे कहा, जो लोग एक रुकी हुई और बेजान सोच के साथ जीते हैं, वे वास्तव में जीवन का पूरा आनंद नहीं ले सकते। हमने अपनी सोच की सीमाओं को ही अपनी दुनिया की सीमाएं मान लिया है। कोई भी देश अपनी वास्तविक क्षमता को तभी पहचान पाता है, जब वह अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने ठीक ऐसा ही करके दिखाया है। गरीबी उन्मूलन से जुड़े पुराने नारों का जिक्र करते हुए, जो केवल फाइलों में ही दबे रह गए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में उस शुरुआती उपहास को याद किया, जब उन्होंने लाल किले से गरीबों के लिए शौचालय बनाने का अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। उन्होंने महिलाओं और माताओं की गरिमा और सुरक्षा के लिए शौचालयों के महत्व पर जोर दिया। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि 12 से 13 वर्षों की अवधि में लगभग 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।

गले मिले, हाथ मिलाया...फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश सेतु का किया उद्घाटन



पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के वैशाली जिले में नीतीश सेतु का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। नीतीश सेतु गंगा नदी पर बना एक एक्स्ट्राडोज्ड केबल-स्टेयड पुल है, जिसे लगभग 4,280 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। 19.7 किलोमीटर लंबी यह परियोजना पटना जिले में एनएच-22 पर स्थित कच्ची दरगाह को वैशाली जिले में एनएच-322 पर स्थित बिदूपुर से जोड़ती है। इसमें 9.7 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल और 10 किलोमीटर लंबी एप्रोच सड़कें शामिल हैं।

यह पुल गंगा नदी को पार करने का एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगा, जिससे मौजूदा महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और उत्तर व दक्षिण बिहार के बीच यात्रा का समय घटेगा। इससे विशेष रूप से राघोपुर दियारा के निवासियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे पटना तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी और स्वास्थ्य सेवा व शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। यह परियोजना कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामानों के परिवहन को भी आसान बनाएगी, बाजारों तक पहुंच बेहतर करेगी और पूरे क्षेत्र में व्यापार-वाणिज्य को बढ़ावा देगी, जिससे बिहार के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश सेतु ने दशकों की मांगों को पूरी कर दी। चिराग ने कहा कि नक्सलवाद का खात्मा कर युवा पीढ़ी को मुख्यधारा से जोड़ने का मार्गदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है।

विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होने तक लोकसभा सीटों की संख्या न बदले: कांग्रेस

नईदिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि देश के हित में लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा बरकरार रखा जाना चाहिए तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस व्यवस्था को तब तक बरकरार रखा जाना चाहिए, जब तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मौजूदा परिस्थितियों में यह देश के हित में है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाए तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाए।

इस व्यवस्था को विकसित भारत का बहुचर्चित लक्ष्य हासिल होने तक स्थिर रखा जाना चाहिए।'' उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक सत्रावसान की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, ''17 अप्रैल, 2026 को पुराना विधेयक भारी मतों से पराजित हो गया था।

किसी को नहीं पता कि नए विधेयक में क्या प्रावधान होंगे।'' कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि सरकार ने परिसीमन के नए प्रस्तावों पर किसी भी राजनीतिक दल के साथ गंभीर और व्यवस्थित तरीके से चर्चा नहीं की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई गई है। रमेश ने कहा कि देश के सामने



आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कहीं अधिक गंभीर चुनौतियां हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा, ''व्यापक और दूरगामी परिसीमन की प्रक्रिया इंतजार कर सकती है।'' उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने 1976 में परिसीमन को 25 साल के लिए टाल दिया था, जबकि वाजपेयी ने 2001 में इसे अगले 25 साल के लिए, यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक स्थगित कर दिया था। रमेश ने प्रधानमंत्री की ओर से 19 नवंबर को फिक्की के सम्मेलन में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जताई गई चिंता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए ''शांत दिमाग'' और विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा लोकसभा की सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा बरकरार रखते हुए महिला आरक्षण लागू करना उचित होगा। कांग्रेस महासचिव का कहना है कि यह व्यवस्था विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होने तक जारी रहनी चाहिए।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत पहले टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट पर

वेलिंगटन। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में ड्राइविंग सीट पर है। तीसरे दिन को खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट पर 486 रन बना लिए हैं। जिससे उनकी कुल बढ़त 118 रनों तक पहुंच गई। ऋषभ पंत 55 रन बनाकर खेल रहे हैं जबकि उनके साथ नाइटवॉचमैन के तौर पर बल्लेबाजी करने आए अंशुल कंबोज को अभी अपना खाता खोलना है। दिन के आखिरी ओवर में कप्तान शुभमन गिल शतक बनाने से चूक गए और 98 रन पर आउट हो गए। उनको जैकब डफी ने क्लीन बोल्ड कर दिया।



इससे पहले उप-कप्तान केएल राहुल ने शानदार शतकीय पारी खेली, और 290 गेंदों पर 136 रन बनाकर कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। वो सेना देश (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। इसके अलावा आज देवदत्त पडिक्कल 175 गेंदों में 80 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके लगाए। इससे पहले जायसवाल 85 रन बनाकर आउट हुए थे।

खास बात ये है कि भारत के टॉप फाइव बल्लेबाजों ने पचास प्लस स्कोर किया। जो कि भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सेना देश में पहली बार हुआ। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को तीसरे दिन भी काफी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन वो भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने से नहीं रोक सके। चारों तेज गेंदबाज एक-एक विकेट लेने में ही सफल रहे। ब्लैककैप्स ने अपनी पहली पारी में हेनरी निकोल्स के नाबाद 175 रन और ग्लेन फिलिप्स के 118 रनों की बदौलत 368 रन बनाए थे। चौथे दिन का खेल भारत के लिहाज से बहुत अहम होगा, क्योंकि उस भारतीय बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर इंग्लैंड को हराने की पूरी कोशिश करेंगे और चाहेंगे की उनका चौथी पारी ना खेलनी पड़े।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

यश बैंक और नोवियो ने लॉन्च किया खास डुअल क्रेडिट कार्ड

मुंबई। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक, यश बैंक और क्रेडिल्लो फाइनेंशियल टेक्नालॉजी के कंज्यूमर क्रेडिट प्लेटफॉर्म नोवियो ने शनिवार को यश बैंक नोवियो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। इस कार्ड में एक ही क्रेडिट लिमिट के अंदर एक फिजिकल मास्टरकार्ड और एक वर्चुअल रूपे कार्ड मिलता है। ग्राहक अपनी ज़रूरतों और मिलने वाले फायदों के आधार पर इन दोनों पेमेंट नेटवर्क में से किसी एक को चुन सकते हैं। वे एक ही क्रेडिट अकाउंट के ज़रिए दोनों कार्डों को मैनेज कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी पसंद के अनुसार कार्ड चुनने की ज़्यादा आज़ादी मिलती है। यश बैंक नोवियो क्रेडिट कार्ड के लॉन्च के साथ, नोवियो अब अनसिक्योर्ड क्रेडिट की सुविधा भी दे रहा है। इससे योग्य ग्राहकों को अपनी बदलती वित्तीय ज़रूरतों के हिसाब से क्रेडिट पाने के और भी विकल्प मिलते हैं।

7 प्रतिशत की रफ्तार से दौड़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था : रिपोर्ट

नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक राहत भरी और साथ ही सतर्क करने वाली खबर सामने आई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च (कैपेक्स), मजबूत घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र (सर्विसेज) की तेज रफ्तार इस विकास दर को सहारा दे रही है। हालांकि, आम आदमी और उद्योग जगत के लिए महंगाई का दबाव अब भी सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, जिसके चलते आने वाले दिनों में कर्ज और महंगे हो सकते हैं। ब्रिकवर्क रेटिंग्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत की विकास रफ्तार को घरेलू मजबूती और सेवा निर्यात का मजबूत संबल मिल रहा है। अक्टूबर में सर्विसेज पीएमआई बढ़कर 55.8 पर पहुंच गया।

शेयर बाजार में अगले हफ्ते डिविडेंड का मौका

नईदिल्ली। अगले हफ्ते शेयर बाजार की तीन कंपनियां अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देंगी। इनमें पशुपति कॉटस्पिन, ब्रज आयरन एंड स्टील और फ्यूजन सीएक्स शामिल हैं। इन कंपनियों ने अंतरिम और फाइनल डिविडेंड की तारीखें तय कर दी हैं। तीनों कंपनियों की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट 23, 25 और 27 नवंबर 2026 को है। जानकारी के मुताबिक, पशुपति कॉटस्पिन हर शेयर पर 0.02 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। ब्रज आयरन एंड स्टील के शेयरधारकों को 0.60 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड मिलेगा। वहीं, फ्यूजन सीएक्स ने हर शेयर पर 0.75 रुपये के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। पशुपति कॉटस्पिन लिमिटेड ने 0.02 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी के शेयर की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट 23 नवंबर 2026 तय की गई है। शेयर बाजार में कंपनी का नाम पशुपति है।

चीन को पुराने चिप्स की बिक्री पर नहीं लगेंगे नए प्रतिबंध

नई दिल्ली। वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार और अमेरिका-चीन तकनीकी टकराव के बीच अमेरिकी सरकार ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) स्कॉट बेसेंट ने साफ किया है कि चीन को एनवीडिया के पुराने चिप्स बेचने पर अब और नए प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। यह बयान ट्रंप प्रशासन की की ओर से चीन की नवीनतम सेमीकंडक्टर्स तक रिमोट एक्सेस (पहुंच) को रोकने के फैसले के ठीक बाद आया है। ट्रंप के साथ एशिया दौरे से लौटने के बाद सीएनबीसी को दिए एक साक्षात्कार में स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चिप निर्यात को लेकर जरूरी और उचित पाबंदियां पहले से लागू हैं। बेसेंट के मुताबिक, चीनी कंपनियों की अत्याधुनिक चिप्स तक रिमोट पहुंच को प्रभावी ढंग से सीमित कर दिया गया है।

बैंकों का एनपीए घटा, लेकिन कमाई पर दबाव

तमाल बंद्योपाध्याय

आज किसी भी बैंक के ट्रेजरी फ्लोर में जाइए, तो आपको डीलरों के बीच राहत का भाव महसूस होगा। अक्टूबर के अंत में लगभग 7.5 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद, 10-वर्षीय बेंचमार्क सरकारी बॉन्ड यील्ड अब 7.1 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत के बीच स्थिर हो रही है।

बॉन्ड की कीमतें और यील्ड विपरीत दिशाओं में चलती हैं- जब यील्ड बढ़ती है, तो बॉन्ड का मूल्य गिर जाता है, जिससे बैंकों की ट्रेजरी आय पर मार्क-टु-मार्केट (एमटीएम) का असर पड़ता है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ट्रेजरी आय में सितंबर तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो बॉन्ड यील्ड में शुरुआती वृद्धि और रुपये के अवमूल्यन दोनों के कारण हुई।

केयरएज रेटिंग्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर तिमाही में चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राजकोषीय आय में वार्षिक आधार पर 61.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। निजी क्षेत्र के बैंकों में 65.7 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 59.4 प्रतिशत की गिरावट से कहीं अधिक है। एक और चिंताजनक मुद्दा कम ब्याज दर वाले चालू खाता और बचत खाता (कासा) जमाओं में लगातार हो रही कमी है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 48.4 प्रतिशत के कासा अनुपात के साथ उद्योग में अग्रणी है, इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र (46.47 प्रतिशत), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (44.65 प्रतिशत), आईडीबीआई बैंक (43.82 प्रतिशत), जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक (41.97 प्रतिशत) और आईओबी (40.71 प्रतिशत) हैं। बड़े ऋणदाताओं में, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने कम से कम 38 प्रतिशत का कासा



अनुपात बनाए रखा।

बैंकरों के लिए एक और बड़ी समस्या शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में लगातार हो रही गिरावट है। एचडीएफसी बैंक का एनआईएम सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 11 आधार अंक (बीपीएस) और तिमाही आधार पर 10 बीपीएस गिरकर 3.16 प्रतिशत पर आ गया, जो अब तक का सबसे कम है। आईसीआईसीआई बैंक का मार्जिन सालाना आधार पर 12 बीपीएस और तिमाही आधार पर 18 बीपीएस गिरकर 4.18 प्रतिशत पर आ गया। ऐक्सिस बैंक में इससे भी अधिक गिरावट देखी गई-सालाना आधार पर 37 बीपीएस और तिमाही आधार पर 10 बीपीएस गिरकर 3.36 प्रतिशत पर आ गया। एसबीआई ने इस रुझान के विपरीत प्रदर्शन किया- इसका घरेलू एनआईएम तिमाही आधार पर 11 बीपीएस बढ़कर 3.11 प्रतिशत पर पहुंच गया।

कासा और एनआईएम में लगातार गिरावट गहरे संरचनात्मक बदलावों की ओर इशारा करती है। कासा में लगातार गिरावट भारतीय बचतकर्ताओं द्वारा अपने पैसे के उपयोग के तरीके में एक मूलभूत बदलाव को दर्शाती है, जिससे बैंकों को बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण उच्च वित्तपोषण लागतों के अनुकूल होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन बैंकों की बैलेंस शीट पर एक ऐसा मापदंड है जो कहीं अधिक गहन संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत देता है और यह दर्शाता है कि बैंकिंग व्यवसाय किस प्रकार विकसित हो रहा है। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है- यह फंसी परिसंपत्तियों में लगातार और स्थिर गिरावट है।

वर्तमान में केवल एक पीएसबी की शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात 0.5 प्रतिशत से अधिक है, जबकि पांच निजी क्षेत्र के बैंकों का अनुपात इससे अधिक है। ये छह बैंक हैं बंधन बैंक (92 बीपीएस), इंडसइंड बैंक (83 बीपीएस), कर्णाटका बैंक (74 बीपीएस), डीसीबी बैंक (73 बीपीएस), पंजाब ऐंड सिंध बैंक (61 बीपीएस) और जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक (51 बीपीएस)। सितंबर तिमाही में सूचीबद्ध सभी बैंकों ने अपने शुद्ध एनपीए में सालाना गिरावट दर्ज की। आईडीबीआई बैंक को छोड़कर बाकी सभी बैंकों ने सालाना और तिमाही दोनों आधार पर गिरावट दर्ज की। आईडीबीआई बैंक का शुद्ध एनपीए अनुपात 17 बीपीएस रहा, जो एक साल पहले के 21 बीपीएस से कम है, हालांकि जून तिमाही के 16 बीपीएस से थोड़ा अधिक है।

मुख्यमंत्री साय का जनदर्शन 26 नवंबर को



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनदर्शन कार्यक्रम गुरुवार, 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन, रायपुर में प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित जनदर्शन में मुख्यमंत्री श्री साय आमजनों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं एवं मांगें सुनेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय जनदर्शन के दौरान नागरिकों की समस्याओं से रूबरू होंगे तथा उनके त्वरित एवं यथोचित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। जनदर्शन में आमजन अपनी समस्याओं, मांगों और सुझावों को सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकेंगे।

दो दिवसीय भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक आज से

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक 22 एवं 23 नवंबर को भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आहूत की गई है। युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया सहित बड़ी संख्या में भाजयुमो पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बैठक में संगठनात्मक विषयों, आगामी कार्यक्रमों एवं कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा होगी।

क्या कांग्रेस आलाकमान यादव को प्रदेश अध्यक्ष बना रहा है या बघेल के दबाव में सूची से नाम काटा गया



रायपुर । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा हाल ही में जारी की गई राष्ट्रीय सचिवों की सूची से छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का नाम न होने को लेकर कांग्रेस की आंतरिक स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. किरण बघेल ने सवाल उठाए हैं। डॉ. बघेल शनिवार को यहाँ एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा कर रही थीं। श्रीमती बघेल ने कहा कि हाल ही में जारी की गई एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिवों की सूची से देवेंद्र यादव जैसे महत्वपूर्ण नेता का नाम गायब है। इस घटनाक्रम पर दो मुख्य सम्भावनाएँ जताते हुए श्रीमती बघेल ने कांग्रेस नेतृत्व से सवाल पूछा और कहा कि या तो कांग्रेस आलाकमान और राहुल गांधी देवेंद्र यादव को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दबाव में उनका नाम सूची से काटा गया है। श्रीमती बघेल ने कहा कि सूची जारी होने के बाद बघेल के ओएसडी द्वारा सोशल मीडिया पर बाप तो बाप होता है जैसा पोस्ट किया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि बघेल और यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

शिवांगी के शोध से सुरक्षित होगा मातृत्व, आम लोगों को मिलेंगी सस्ती और कारगर प्रसवपूर्व जांच सुविधाएं

रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), रायपुर के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की शोधार्थी शिवांगी दीवान ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐसा महत्वपूर्ण शोध कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, जिसका सीधा लाभ भविष्य में आम परिवारों और गर्भवती महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मृदु साहू के मार्गदर्शन में फिटल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सिग्नल एनालिसिस यूजिंग इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग टेक्निक्स विषय पर यह शोध पूरा किया है, जिससे गर्भस्थ शिशु की धड़कनों की जांच पहले से कहीं अधिक आसान, सुरक्षित और किफायती होगी। अक्सर गर्भावस्था के दौरान मां की धड़कन और अन्य शारीरिक गतिविधियों के कारण गर्भस्थ शिशु की हृदय गति का स्पष्ट डेटा मिलना चुनौतीपूर्ण होता है। शिवांगी के इस शोध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी भी तरह की इनवेसिव प्रक्रिया यानी चीरे व दर्द के बिना, केवल गर्भवती महिला के पेट पर लगे सामान्य इलेक्ट्रोड की मदद से शिशु की हृदय गतिविधियों का अध्ययन किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग की मदद से यह तकनीक शिशु के कमजोर संकेतों को स्पष्ट रूप से अलग कर लेती है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत की पल-पल की सही जानकारी मिल सकेगी। आम लोगों के लिए इस शोध का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे गर्भस्थ शिशु में होने वाली किसी भी हृदय संबंधी समस्या या अनियमित धड़कन की पहचान शुरुआती चरण में ही हो सकेगी। जोखिमपूर्ण गर्भावस्था यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों में डॉक्टरों को समय रहते सटीक जानकारी मिलने से वे तुरंत सही इलाज शुरू कर पाएंगे। इससे प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं और शिशु मृत्यु दर को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी।

राडा का भव्य दीपावली मिलन समारोह हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ संपन्न

रायपुर। रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (राडा) द्वारा हर वर्ष की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी भव्य दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए ऑटोमोबाइल डीलर्स ने अपने परिवारजनों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह में सभी सदस्यों एवं उनके परिवारों ने एक-दूसरे को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं तथा दीप प्रज्वलित कर दीपावली की खुशियों और उल्लास को साझा किया। पूरा आयोजन दीपों की रोशनी, आपसी सौहार्द और पारिवारिक आत्मीयता से जगमगा उठा। इस अवसर पर राडा के अध्यक्ष श्री कैलाश खेमानी ने सभी सदस्यों एवं उनके परिवारजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने कार्यक्रम को सफल एवं यादगार बनाने के लिए राडा की पूरी टीम, पदाधिकारियों एवं आयोजन से जुड़े सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राडा की असली ताकत उसकी एकजुटता, आपसी सहयोग और सदस्यों के पारिवारिक संबंधों में निहित है। कार्यक्रम में बच्चों के मनोरंजन के लिए विशेष Kids Game Zone बनाया गया था, जहां बच्चों ने विभिन्न खेलों और मनोरंजक गतिविधियों का भरपूर आनंद लिया। वहीं सभी परिवारों के लिए विशेष रूप से फैमिली गेम्स आयोजित किए गए, जिनमें सदस्यों और उनके परिजनों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।



156 शोध परियोजनाओं में बाल वैज्ञानिकों ने दिखाई प्रतिभा, राष्ट्रीय स्तर के लिए 16 बाल वैज्ञानिकों का चयन

बाल वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन देने के लिए विश्वविद्यालय के द्वार सदैव खुले: कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला



रायपुर। छत्तीसगढ़ के बाल वैज्ञानिकों की रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और नवाचार की प्रतिभा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के संकल्प के साथ 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2026 के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में उत्साहपूर्ण समापन हुआ। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के सहयोग से 20 एवं 21 नवम्बर को आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए बाल वैज्ञानिकों ने अपनी शोध परियोजनाओं और वैज्ञानिक मॉडलों के माध्यम से प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राज्य स्तरीय आयोजन में कुल 156 शोध परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिनका विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 15 विषय विशेषज्ञों ने मूल्यांकन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वरिष्ठ वर्ग के 10 एवं कनिष्ठ वर्ग के 6 सहित कुल 16 बाल वैज्ञानिक समूहों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया गया।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल ने बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक बनने के लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने आसपास की घटनाओं को ध्यानपूर्वक देखना, उनके कारणों को समझना और लगातार प्रश्न पूछना भी आवश्यक है। जिज्ञासा ही नवाचार की वास्तविक आधारशिला है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन केवल प्रतियोगिता में प्राप्त स्थान से न करें। सफलता केवल प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। किसी समस्या को नए दृष्टिकोण से समझना, उसका समाधान खोजना और अपने विचारों को विकसित करना ही वैज्ञानिक उपलब्धि की वास्तविक शुरुआत है। उन्होंने दैनिक जीवन के एक अभिनव उदाहरण का उल्लेख करते हुए बताया कि किस प्रकार अनुपयोगी प्लास्टिक पेन एकत्रित करने के लिए विकसित 'पेन बिन' जैसी छोटी पहल भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। उन्होंने कहा कि नवाचार हमारे आसपास मौजूद है, आवश्यकता केवल सजग दृष्टि और रचनात्मक सोच की है।

छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक श्री प्रशांत कविश्वर ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि विज्ञान और नवाचार का उद्देश्य केवल नई तकनीक विकसित करना नहीं, बल्कि समाज के सामने उपस्थित समस्याओं के व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक समाधान खोजना भी है। प्रत्येक बड़ी वैज्ञानिक खोज की शुरुआत एक छोटे प्रश्न, जिज्ञासा या समस्या से होती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को सही प्रश्न पूछने, समस्याओं के कारणों को समझने और मार्गदर्शक शिक्षकों की सहायता से वैज्ञानिक पद्धति द्वारा उनका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। अनुसंधान के दौरान प्राप्त निष्कर्षों का परीक्षण तथा उनमें निरंतर सुधार करना भी वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग की निदेशक डॉ. मंजू सिंह ने बाल वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस आयोजन में भाग लेने वाला प्रत्येक विद्यार्थी विजेता है। बाल वैज्ञानिकों के नवीन विचारों और प्रस्तुतियों से शिक्षकों एवं विशेषज्ञों को भी नई बातें सीखने का अवसर मिला। इन बच्चों की प्रतिभा यह विश्वास जगाती है कि आने वाले समय में इन्हीं में से कोई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, बड़ा आविष्कारक या नोबेल पुरस्कार जैसी प्रतिष्ठित उपलब्धि प्राप्त करने वाला शोधकर्ता भी बन सकता है।

सही प्रश्न पूछने और वैज्ञानिक तरीके से समाधान खोजने की प्रवृत्ति विकसित करें बच्चे: महानिदेशक प्रशांत कविश्वर

जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत को सहेजकर नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी: केदार कश्यप

रायपुर। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर रायपुर के पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में जनजातीय गौरव दिवस 2026 एवं वीरांगना शौर्य उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास के साथ महान जनजातीय नायकों के योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता तथा संसदीय कार्य मंत्री एवं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत को सहेजकर नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है।



मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास त्याग, संघर्ष, साहस और बलिदान की गौरवशाली गाथाओं से भरा हुआ है। जनजातीय वीर नायकों और वीरांगनाओं ने जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास और योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने के उद्देश्य से जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की गई।

श्री कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संवेदनशील नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के उत्थान, संस्कृति के संरक्षण और दूरस्थ अंचलों के सर्वांगीण विकास को नई गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विश्वास और विकास का नया वातावरण बन रहा है।

उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, अमर शहीद गुंडाधुर, रानी कमलापति के जीवन से प्रेरणा लें। साथ ही अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों पर गर्व करते हुए इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रूपसिंह मंडावी ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जनजातीय समाज के अधिकारों, अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

रिव्यू मिशन के तहत केंद्रीय टीम करेगी छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा

रायपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 18वें कॉमन रिव्यू मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए केंद्रीय टीम प्रदेश के भ्रमण पर रहेगी। इस संबंध में रायपुर स्थित



निजी होटल में केंद्रीय टीम के सदस्यों की ब्रीफिंग आयोजित की गई। कॉमन रिव्यू मिशन के अंतर्गत केंद्रीय टीम प्रदेश के सुकमा एवं बलौदाबाजार जिलों का भ्रमण कर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता, क्रियान्वयन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जमीनी स्थिति का आकलन करेगी। भ्रमण के लिए टीम को दो दलों में विभाजित किया गया है, जो संबंधित जिलों में स्वास्थ्य संस्थानों एवं स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेंगे। ब्रीफिंग के दौरान मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, मलेरिया, टीबी सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं प्रगति से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। केंद्रीय टीम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र , NIHFW, ICMR-NIV, CCRAS तथा अन्य राष्ट्रीय एवं सहयोगी संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं। केंद्रीय टीम में डॉ. रघुराम राव , डॉ. ओ. पी. कंसल, डॉ. मिहिर कुमार मलिक, डॉ. अशोक मुनिवेंकटप्पा, डॉ. निधि तिवारी, डॉ. सुरभि यादव, डॉ. अतुल मित्तल , डॉ. शिल्पा सिंह एवं सुश्री कल्याणी दत्ता सहित विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के मीडिया प्रकोष्ठ की 64 सदस्यीय कार्यकारिणी का हुआ विस्तार

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेंद्र साहू की अनुशंसा पर पत्रकारों को मिली संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी



नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक गतिविधियों को व्यापक स्तर पर जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में मीडिया प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेंद्र साहू की अनुशंसा पर प्रदेश संयोजक, प्रदेश महामंत्री सहित कुल 64 पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस विस्तार में प्रदेश के विभिन्न जिलों और शहरों में कार्यरत पत्रकारों को शामिल किया गया है। उक्त जानकारी प्रदेश साहू संघ, मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार साहू ने दी।

दिलीप कुमार साहू प्रदेश संयोजक, अशोक कुमार साहू प्रदेश महामंत्री

मीडिया प्रकोष्ठ में दिलीप कुमार साहू को प्रदेश संयोजक और अशोक कुमार साहू को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों पदाधिकारियों के समन्वय से प्रदेश कार्यकारिणी की गतिविधियों को गति देने, विभिन्न जिलों के पत्रकारों के बीच संपर्क मजबूत करने और संगठन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा।

सलाहकार मंडल में पांच वरिष्ठ पत्रकार

सलाहकार के रूप में कौशल स्वर्णबेर, चंदन साहू, प्रदीप साहू, कमलेश साहू और राहुल सोन को शामिल किया गया है।

प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर 10 पत्रकारों को जिम्मेदारी

प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में संतोष साहू (रायपुर), राकेश साहू (गरियाबंद), दीनदयाल साहू (भिलाई), अनंतराम साहू (रायपुर), संदीप साहू (राजनांदगांव), संतोष साहू (कसडोल), सतीश साहू (जगदलपुर), चूड़ामणि साहू (रायगढ़), डॉ. भूपेंद्र कुमार साहू (धमतरी) और महेंद्र साहू (रायपुर) को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बिलासपुर-झारसुगुड़ा चौथी रेल लाइन परियोजना के कार्यों को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

चांपा-जांजगीर नैला सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग का कार्य किया जाएगा



रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रेल अधोसंरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच 206 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन परियोजना का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। यह रेल मार्ग देश के उत्तर एवं दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण एवं व्यस्त रेल कॉरिडोर है।

इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूर्ण होने से रेल मार्ग की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे बढ़ते यात्री एवं माल यातायात का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा तथा ट्रेनों के सुचारू एवं समयबद्ध परिचालन को भी गति मिलेगी। साथ ही, भविष्य में नई यात्री ट्रेनों के परिचालन के लिए अतिरिक्त रेल मार्ग उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलेगी।

इस परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने हेतु बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन के चांपा स्टेशन को चौथी रेल लाइन से जोड़ने हेतु नॉन-इंटरलॉकिंग का महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही चांपा-जांजगीर नैला सेक्शन में रेल परिचालन को और अधिक सुरक्षित, सुगम एवं प्रभावी बनाने के लिए ऑटो सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित करने का कार्य भी किया जाएगा। इन कार्यों के फलस्वरूप कुछ ट्रेनों का परिचालन अल्पकालिक बाधित रहेगा।

विश्व कल्याण के कार्य में कन्याओं को समर्पित करने वाले माता-पिता भाग्यशाली हैं

समर्पित होने वाली कन्याओं के अभिभावकों का शांति शिखर में हुआ अभिनंदन



रायपुर। ब्रह्माकुमारीज़ के शांति शिखर परिसर में शनिवार को ब्रह्माकुमारी जीवन अपनाने का निर्णय लेने वाली 45 कन्याओं के अभिभावकों का अभिनंदन किया गया। आध्यात्मिक गरिमा से परिपूर्ण इस आयोजन में माता-पिता के साथ बड़ी संख्या में उनके परिवारजन उपस्थित थे।

समारोह में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी जयन्ती दीदी, क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्माकुमारी हेमलता दीदी, प्रयागराज से पधारी धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा ब्रह्माकुमारी मनोरमा दीदी, माउण्ट आबू से आयी ब्रह्माकुमारी हंसा दीदी, गांधीनगर की वरिष्ठ राजयोगिनी कैलाश दीदी, मेरठ से लक्ष्मी दीदी एवं मूर्ति दीदी, भिलाई की ब्रह्माकुमारी आशा दीदी, उज्जैन की ब्रह्माकुमारी उषा दीदी, इन्दौर की ब्रह्माकुमारी करूणा दीदी, रायपुर संचालिका ब्रह्माकुमारी सविता दीदी, धमतरी की ब्रह्माकुमारी सरिता दीदी, जगदलपुर की मंजूषा दीदी, बिलासपुर से मंजू दीदी, दुर्ग से रीता दीदी सहित देश-विदेश एवं मधुबन से आए अनेक वरिष्ठ भाई-बहन तथा समर्पित कन्याओं के परिजन उपस्थित रहे। संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी जयंती दीदी ने कहा कि विश्व कल्याण के कार्य में अपनी कन्याओं को समर्पित करने वाले माता-पिता वास्तव में परम भाग्यशाली हैं। इन कन्याओं का जीवन साधारण नहीं है। परमात्मा से अविनाशी संबंध जोड़कर ये स्वयं के जीवन से हजारों-लाखों आत्माओं को सुख-शांति का मार्ग दिखाते हुए विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनेंगी। इन बहनों का जीवन समस्त समाज और विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्माकुमारी हेमलता दीदी ने कहा कि इन बहनों का दृढ़ संकल्प सराहनीय है। वे पवित्रता और मर्यादाओं का पालन करते हुए संस्था के साथ अपने परिवार का नाम भी रोशन करेंगी। प्रयागराज से पधारी धार्मिक विंग की अध्यक्ष ब्रह्माकुमारी मनोरमा दीदी ने कहा कि कलियुग में आधुनिक मीरा के रूप में कन्याओं का परमात्मा के प्रति समर्पण साहस, वीरता और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है।



नृत्य-नाटिका ने किया भावुक

कार्यक्रम का शुभारंभ रायपुर के बाल कलाकारों की भावपूर्ण नृत्य-नाटिका ' 'एक चिट्ठी माता-पिता के नाम'' से हुआ। जिसकी प्रेरणादायी प्रस्तुति ने उपस्थित अभिभावकों को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान समर्पित हो रही कन्याओं के माता-पिता का संस्था द्वारा विशेष सम्मान व अभिनंदन किया गया।

माता-पिता ने कहा बेटियों का ब्रह्माकुमारी बनने का निर्णय सराहनीय

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.